

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1979

खण्ड 1 अंक 19

अधिकृत विवरण

## विशय सूची

वीरवार, 29 मार्च, 1979

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(19)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(19)21
ध्यानाकर्षण सूचना:—	
(1) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अभिकथित कार्यवाहियों सम्बन्धी	(19)22
2. कृषि उपज की कम कीमतों तथा कृषि इन-पुटस तथा कंज्यूमर गुडज की चढती हुई कीमतों सम्बन्धी	(19)24
3. पंजाब स्टेट री-आग्रेनाइजे टन एक्ट, 1966 के अधीन कारपोरेट बौडिज में हरियाणा के हिस्से संबंधी	(19)24
वाकआउट	(19)28
कमेटी आन दि वैंल्फेयर आफ कास्टस एंड रिटायर्ड्स ट्राइब्ज की चौथी रिपोर्ट पर ध्यान देना	(19)30
गैर-सरकारी प्रस्ताव	(19)30

1. राज्य में उच्च भारी प्रशासन में वृद्धि रोकने के लिए आई0ए0एस0 काडर की संख्या में और वृद्धि न करने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	
सभापति द्वारा घोषणा	(19)44
गैर-सरकारी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	
2. मुख्य मंत्री का एम0एल0ए0 फ्लैट्स में रिफिट न करने सम्बन्धी	(19)45
3. राज्य में पिछड़ी श्रेणियों के लिये सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये पदों के आरक्षण सम्बन्धी	(19)51
4. डी0एस0पोज0 के सिलैबान ग्रेड के वेतनमान एच0सी0सए0 (एग्जैक्टिव) के बराबर लाने तथा सिलैबान ग्रेड पदों की संख्या बढ़ाने सम्बन्धी	(19)52
5. फसलों के लाजमी बीमों के लिये कानून बनाने सम्बन्धी	(19)57

# हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 29 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक , हरियाणा सभा हाल , विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

## तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहिबान, अब सवाल होंगे।

### **Opening of Primary Schools and Adult Education Centres**

**\*926. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of Government Primary Schools and Adult Education Centres opened during the period from the 4<sup>th</sup> July, 1977 to 30<sup>th</sup> June, 1978, in the State;

(b) whether it is a fact that there are certain villages in the State where even Primary School does not exist; if so, the name of such villages, and

(c) whether any benefit is being derived from the newlyh opened Adult Education Centres?

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

- (क) 1. प्राथमिक पाठशाला 1  
2. प्रौढ़ शिक्षा 600

(ख) जी हां, हरियाणा राज्य में 286 गांव हैं, जिनकी सूची अनैक चर 'ए' पर है जो कि सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ग) जी हां। इन केन्द्रों में इससमय 63182 प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

अनैक चर 'ए'

स्कूल रहित गांवों की जिलावार सूची

क्रम संख्या	जिला का नाम
जिला अम्बाला	
1	अलीपूर
2	भोरगढ़
3	गोली
4	मालकपुर

5	हररा
6	बूटगढ़
7	नालागढ़ माजरी
8	बोलतपूर
9	बैनीपूर
10	टोडरपूर
11	गुलाबगढ़
12	सुखपुरा
13	सामापूर
14	रैतगढ़
15	बटनपुरी
16	हसनपुरी
17	सुखदासपूर
18	बम्दारपूर
19	मोलीमाजरा

20	पटासगढ
21	भान्सदरपूर
22	गोलपूरा
23	मुरादनगर
24	सुलतानपूर
25	बडीखेडी
26	तसरौला
27	गोबिन्दपूरा
28	सदापूर
29	राबदसापुर
30	जूथेरी
31	हालीवाला
32	परोदरी
33	लापरा
34	महमूदपूर

35	तयालगढ रामपुर
36	रामपुर
37	नागल
38	काकरु
39	मनसूरपुर
40	भाहपुर
41	लाहोरोन्दी
42	सीतामाजरा
43	रामनगर
44	कोडीअला
45	बगलारी
46	मुहापतपुर
47	रामसु
48	कजीयाना
49	कैदारपुर



50	लोहगढ़
51	जूरीयन
52	फ़िरोजापुर खुद
53	डिम्डामा
54	फतेहपुर
55	खरक्यू
56	रायपूर
57	जोदपुर
58	नवानगर
59	सिंहपुरा
60	राजपुरा
61	अलीपुर
62	रामगढ़
63	माजरा
64	भाहबादीयापुर

65	डूकडीवाला
66	टलीपूर
67	हैदरपूर
68	बसन्तौर
69	छीतपूर
70	टाबरी
71	सुन्दर बहादुरपुर
72	हारीवार
73	जैरामपुर खालसा
74	मीरपुर
75	सपोलिया
76	बरोली, माजरा
77	बी ानगढ़
78	रसूलपुरा
79	अलाउदीनमाजरा

80	सैनीमाजरा
81	बीरगन
82	गौसीयन
83	बाम्बा
84	नेकतपूर
85	कानडीडिया
86	जारसुहिया
87	वसीन माजरा
88	पहाडपुर
89	सलीमपुर
90	सुलतानपुर
91	फिरोजपुर अरीयन
92	मिलक
93	सायनमाजरा
94	अहमदपुर

95	खरकी
96	पंजौरी
97	सोलटी
98	पराल
99	बुर्ज
100	टांका माजरा
101	राजपुर
102	असगरपुर
103	गुडोपुर
104	कनडीयावाला
105	छोटी टीब्बी
106	नवां गावं
107	रायपुर विरान
108	टपरियन सानीनी
109	अराईयांवाला

110	बाल मजरा
111	भाखरी
112	छोटी बसी
113	बेलवाली
114	चमेली माजरा
115	छोटी रसापुर
116	लोटन कालौनी
117	राव माजरी
118	राजू माजरी
119	काटली
120	टीकरी
121	डबसू
122	बेलवाली
123	नागई मोगी नई
124	कि अनगढ़

125	कोटली
<b>जिला भिवानी</b>	
1	भानीनवान राजगढ़
2	भानी अहीरान
3	भानी पुनतः
4	सहजमानपुर
5	धधरवास
<b>जिला गुड़गावं</b>	
1	बहरोला
2	नगला कनजर
3	अमलजाबाद
4	नगला कहीम
5	नगला कनजरपुजोरा
6	पीरगढ़ी
7	भोरन का नगला

8	रटक नगर
9	सती का नगला
10	न्यू कालोनी रेलवे रोड (होडल)
11	बरीयापटी(होडल)
12	पारली
13	जोगीपुर
14	मनआकी
15	मच्छरौली
16	बेरकपुर
17	अनवाका
18	पाल्ला
19	मियनवाली
20	खुनहेरकच्छा
21	मुदहरमलूका
22	भानीवास देव

23	सारलू
24	केरहरी
25	लाहावास
26	करपुरी
27	ताजपूरा
28	पधा
29	असलालपूर
30	याकवपुर
31	मोसकोला
32	तिलोरोखादार
33	सीनदापुर
34	सोहरावत
35	परलादपुर माजरा खाटोली
36	बापुरनगर (जाहार सेटली)
37	इस्मालपुर



38	डेलापुर
39	कलेरा
40	सढौला
41	टीकोबली
42	थुमोसपूर
43	खटरीका
45	जाकोपुर
46	मोहमदपुर
47	सलालपुर
48	डलैनी
49	मावका
50	मोहमद पीद नगर
51	मोलावास
52	बरेहरी
53	नोमहेरा

54	मेहचन्द
55	साधरा थानी
56	राजपुर
<b>जिला हिसार</b>	
1	थानी भाभन
2	थानी पीरन
3	रीछपुरा
4	नीमरी
<b>जिला जीन्द</b>	
1	फुलिया खुर्द
2	फारैन खुर्द
3	मालिदा खुर्द
<b>जिला कुरुक्षेत्र</b>	
1	अजीत नगर
2	बी ानगढ़ बसरीया

3	रामपुरा
4	खेड़ी ब्राह्मण
5	दीदाखोडी
6	माजरी पुरबिया
7	छारपुर
8	देहरा छाक जागलियन
9	देहरा दूप साडिया
10	देहरा अमृत
11	डाहरी जालियन
12	खाज जनपुर ( गहबाद-I)
13	अजकपुर
14	श्रीनगर
15	बोरीपुर ( गहबाद-II)
16	धमगढ़
17	नानकपुर

18	लनगी
19	करतापुर (रादौर ब्लोक)
20	फतेहगढ
21	धीसपुर
22	छीजीपुर
23	बसन्तपुरा
24	सहजादपुर
25	जोगी माजरा
26	रायसेरा
27	अमलो
28	सीली खुर्द
29	छाकचान्दपुर
30	भागूमाजरा
31	भाहबीरी
32	जैं सिंह माजरा

33	बापदा
34	गुहान (लाडवा ब्लाक)
35	कालाक
36	दुधा
37	टटीरी
38	नखरोजपुर
39	करोली
40	डुगेरी
<b>जिला करनाल</b>	
1	महमूदपूर माजरा
2	जय पहार
3	अम्बा
4	परानवादा
5	जालापुर
6	नगलाखुर्द

7	गोहन बुर्ज
8	करतानपुर
9	भोखपुर पाल
10	पिपलवाली
11	पालनगर
12	रियालपुर
13	गोनिन्दगढ (नीलोखेडी-I)
14	नीरमाजरा
15	रामनगर
16	गोबिन्दगढ (नीसंग)
17	खटाना
18	पुरब्यान (डेरा)
19	मालिकपुर
20	कतूर
21	बुडनपुर

22	कामरो
23	अलीसगरपूत
24	केहलोलपुर
25	खीजपुरा
26	हमीरपुर
27	भावमाजरा
28	भाोतरा
29	कालरी
30	जारोली
31	बाद ाहपुर
32	सिमारपुर
33	दारूसानडातपुर
34	केसी
<b>जिला नारनौल</b>	
1	रधुनाथपुरा

2	भगवानपुरा
3	भवल हरिजन बस्ती
4	जैतपुर की धनी
5	कसौली
6	बाखापुर
7	खारीवाडा
8	कीरारऔथ अफगान
<b>जिला रोहतक</b>	
कोई नहीं	
<b>जिला सोनीपत</b>	
1	छोटी बेनसवान खुर्द
2	बान्दपुर
3	जगदीपुर
4	छन्डाली
5	जेफरपुर



6	भागीपुर
7	भारत
8	गिवासपुर
9	मानकपुर
<b>जिला सिरसा</b>	
1	भामबूर खुर्द
2	खाना कुसवाली
<b>कुल</b>	<b>286</b>

**स्वामी आदित्यवे T:** अध्यक्ष महोदय सारे हरियाणा में पिछले 11 महीने में केवल एक प्राईमरी पाठ ाला खोली गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहुंगा कि इतनी कम पाठ ालाये खोलने कै क्या कारण है जबकि हरियाणा में अभी तक 286 गांव ऐसे है जहां एक भी प्राईमरी पाठ ाला नहीं है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, इन गांवों के अलावा तकरीबन 1500 स्कूल और खोले जाने का सरकार का विचार है। 1980-81 में 330 1981-82 में 580 1982-83 में 585।

**डा० बृज मोहन गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने लिस्ट बताई है इसमें सबसे बैकवर्ड जिला अम्बाला है। इस जिले में 125 गांव हैं जहां कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। यह स्कूल और सड़क के लिहाज से सबसे बैकवर्ड है। क्या इन 125 गांवों में प्राइमरी स्कूल बनाने के लिये प्रैफरेंस दिया जायेगा?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, जहां स्कूलों की कमी है वहां स्कूल खोले जायेंगे। हरियाणा में ऐसे भी गांव हैं जहां अभी तक स्कूल नहीं खोले गये हैं। हरियाणा में हर प्राइमरी स्कूल की औसत दूरी 1.44 किलोमीटर रखी गई है।

**श्रीमती भांति देवी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जो लिस्ट उन्होंने सदन के पटल पर रखी है। इसमें जिला सोनीपत में 9 गांव ऐसे हैं जहां कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। इनमें से मेरे हल्के के भी दो गांव हैं करणपुर और यादवपुर जहां कोई स्कूल नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री आवासित करेंगे कि वहां भी प्राइमरी स्कूल खोल दिये जायेंगे?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कूलों की संख्या बताई गई है इनमें डिस्ट्रिक्ट ऐजुकेशन ऑफिसर को स्कूल खोलने का अधिकार है, जहां 30-35 बच्चे हों और इसके अलावा गांव वाले अकामोडे इन प्रोवाइड करें तो वहां स्कूल खोले जायेंगे।

**श्री भलेराम:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय न बताया है कि एडल्ट ऐजूके इन सेंटर 600 खोले जायेगें। क्या वे बतायेगें कि गोहाने में कोई ऐसा सेंटर खोले जाने के लिये प्रैफरेंस दिया जायेगा?

**श्री हीरानन्द आर्य:** इस लिस्ट में सारा टोटल दिया गया है। इसमें आपके गोहाने का भी होगा। अगर आप कहें तो मैं पढकर सुना देता हूं।

**श्री जगननाथ:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने के लिये मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** एज के बारे में सारी डिटेल्स नहीं है जितनी एज और सर्विसीज में होती है.....

**श्री अध्यक्ष:** मैंबर साहेबान आप से स्टूडेंट्स की एज के बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री हीरानन्द आर्य:** प्रौढ़ शिक्षा में प्रवेश पाने के लिये 15 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिये, इससे उपर की आयु के भी हो सकते हैं।

**श्री हरफूल सिंह:** स्पीकर साहब, फतेहाबाद में यालकी के पास एक ढाणी है जहां सौ पढने वाले हैं। क्या मंत्री जी बतायेगें कि वहां इस प्रकार का स्कूल खोला जायेगा?

**श्री हीरानन्द आर्य:** इसके बारे में लिखकर दें, विचार किया जायेगा?

**मास्टर विठ्ठल प्रसाद:** क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं क्या ये वास्तव में चल रहे हैं या सिर्फ कागजों पर ही हैं?

**श्री हीरानन्द आर्य:** जहां तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के चलने का सवाल है ये तो लोगों के सहयोग से ही चलाये जा सकते हैं। ये पिछले 2 अक्टूबर को ही चलाये गये हैं। अब इनमें से कितने कामयाब होंगे यह तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा।

**चौधरी जगजीत सिंह पोहलू:** क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यह जो एडल्ट ऐजुकेशन है क्या हमारी आज की लड़कियों और कल की माताओं के लिये भी पाठशालायें खोलने का सरकार का कोई विचार है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** गांवों में ये विशेष रूप से महिलाओं के लिये खोले जाते हैं। लड़कियों के लिये विशेष रूप से प्राईमरी स्कूल खोले जायेगें।

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** इसका सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** इसमें क्या विशय पढाये जाते है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके उददे य माननीय सदस्यों को पता होना चाहीये।

**श्री भागी राम:** अध्यक्ष महोदय, कुछ गांव ऐसे है खासकर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जहां एक क्लास से तीन क्लास तक के स्कूल है और वहां कम पढे मास्टर लगे हुये है। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि उन स्कूलों को प्राईमरी स्कूल बना दिया जायेगा?

**श्री हीरानन्द आर्य:** सिरसा जिला का जहां तक संबंध है वहां काफी प्राईमरी स्कूल है, फिर भी जहां नही है वहां बना दिये जायेगें।

**चौधरी संत कंवर:** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने चौधरी हरफूल सिंह जी के सवाल के जवाब में कहा कि यदि गांव वाले बिल्डिंग बना कर देगें और एक सौ बच्चे वहां पढने वाले होगें तो वहां स्कूल खोल दिया जायेगा। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी भी यह बात कई बार कह चुके है लेकिन मै मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब आप भाहर मे स्कूल के लिये बिल्डिंग बना कर देते है तो गांव वालों से कयो बिल्डिंग मांगते है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** इस संबंध में कई बार चर्चा हो चुकी है। हरियाणा में 6 हजार गांव है। अगर उन सीमा में सरकार बिल्डिंग बनाने लगे तो उनका 7 करोड से भी ज्यादा खर्च पडेगा। इतना सरकार नहीं कर सकती है, फिर भी सरकार काफी सहायता देती है।

**श्री मूलचन्द मंगला:** हमारे प्रांत में 286 गांव ऐसे है जहां प्राईमरी स्कूलों की ज्यादा जरूरत है। हम चाहते है कि शिक्षा बढे, गांव में प्राईमरी शिक्षा की ओर खास ध्यान दिया जाये। जिन 286 गांवों में प्राईमरी शिक्षा के लिये स्कूल नहीं है वहां स्कूल खोले जाये।

**श्री अध्यक्ष:** इस बारे में बता दिया गया है।

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, इस लिस्ट में नारनौल में मेरे हल्के के तीन गांव ऐसे है जिनमें कोई प्राईमरी स्कूल नहीं है। अगर उनका नाम बता दिया जाये तो क्या इन गांवों में प्राईमरी स्कूल खोले जायेंगे?

**श्री हीरानन्द आर्य:** यह लिस्ट रेवेन्यू एस्टेटस के मुताबिक बनायी गई है। हो सकता है लोग ढाणी में भी बसते हो। उनको भी इसमें शामिल कर लिया जायेगा। यह तो है नहीं कि आज ही ये स्कूल खोल दिये जायेंगे। जहां स्कूल नहीं है वहां जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने का प्रयत्न किया जायेगा।

**चौधरी ई वर सिंह:** अगर कोई पंचायत स्कूल के लिये बिल्डिंग बना कर दे देती है तो क्या वहां इसी पढाई के सै न में स्कूल खोल दिया जायेगा?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, 1980-81 में जिस गांव में बच्चों की संख्या पूरी होगी ओर बिल्डिंग उपलब्ध होगी वहां पर स्कूल जरूर खोल दिये जायेगे ।

**चौधरी खुर गिद अहमद:** स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि 286 गांव ऐसे है जिनमें स्कूल नहीं है। इस जवाब के मुताबिक अभी तक एक ही प्राइमरी स्कूल खुला हैं। क्या मंत्री जी कोई मुकर्रर टाईम बतायेगे कि इन 286 गांवों में कब तक स्कूल खोल दिये जायेगे?

**Mr. Speaker:** I must request the Hon. Member to pay attention to what the hon. Minister replies. उन्होंने प्रोग्राम दिया है कि 1979-80 में इतने खोले जायेगे और 1980-81 में इतने खोले जायेगे तथा 1981-82 में इतने खोले जायेगे।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा:** अध्यक्ष महोदय, एडल्ट ऐजुके न पर बडा जोर दे रहे है लेकिन प्राइमरी ऐजुके न की तरफ कम ध्यान दिया गया है। क्या मंत्री जी बतायेगे कि कयो न प्राइमरी ऐजुके न को कम्पलसरी कर दिया जाए कयोकि एडल्ट ऐजुके न सेंटर तो फिर भी खोले जा सकते है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में तो पहले भी जवाब दिया जा चुका है कि एडल्ट ऐजुकेशन प्रोग्राम नैशनल पालिसी के तहत है और उसके तहत ही सारे देश का यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है लेकिन हरियाणा ने ड्राप आउट को बंद करने के लिये 9 से 14 साल के बच्चों के लिये ऐजुकेशन का प्रबन्ध किया है जिससे एडल्ट ऐजुकेशन की समस्या ही न रहे।

**चौधरी खुरशिद अहमद:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है वह किस जगह पर खोला गया है?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, यह स्कूल कुरुक्षेत्र जिले में 11-8-78 को खोला गया है।

**चौधरी लाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, नारायणगढ़ और कालका में छोटे छोटे गांव हैं और वहां के लोग बहुत गरीब हैं। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि वहां पर प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, नारायणगढ़ का जरूर ध्यान रखा जायेगा।

**स्वामी आदित्यवेदी:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कहां कहां खोले गये हैं और किस आधार पर खोले गये हैं?



श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका अलग से नोटिस दिया जाये।

**Disparity in the Pay-scales of Tracers and Draftsmen**

**\*1163. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether there is any disparity in the pay-scales of Tracers, Draftsmen, Head Draftsmen and Circle Draftsmen working in the P.W.D. (B&R) and Haryana State Electricity Board;

(b) if reply to part (a) be in affirmative the reason therefor; and

(c) whether there is any proposal under consideration to remove this disparity?

**लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):**

(क) जीं हां, केवल ट्रेसरज के पदों को छोट कर जो पद हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार किसी विशेष काडर का वेतनमान राज्य की अन्य सेवाओं के लिये दिये गये वेतनमानों के आधार पर निर्धारित करती है ओर वेतन निर्धारण संतोधन का मामला निगमों और स्वायत्त संस्थाओं जैसे कि राज्य बिजली बोर्ड के वेतनमानों के साथ नहीं जोडा जाता।

(ग) जी नहीं।

**डा० बृज मोहन गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, इनके आफिस में टैक्नीकल स्टाफ भी होता है और ना-टैक्नीकल स्टाफ भी होता है। टैक्नीकल स्टाफ में ओवरसियर, ड्राफ्टमैन और दूसरे आफिसर्ज वगैरह आ जाते हैं और नान-टैक्नीकल स्टाफ में क्लर्क, असिस्टेंट, डिप्टी, सुप्रिन्टेंडेंट और सुप्रिन्टेंडेन्ट आ जाते हैं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नान-टैक्नीकल स्टाफ के ग्रेड में भी कोई डिस्पैरिटी है?

**श्री अध्यक्ष:** इस सवाल का तो नोटिस देना चाहिये।

**श्रीमती भांति देवी:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या यह सत्य है कि उनके वेतनमानों का अन्तर रोकने के लिये एक तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त हुई थी और उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट न करके किसी एक बड़े अधिकारी ने वह मामला रफा दफा कर दिया?

**श्री लछमन सिंह:** स्पीकर साहब, उस वक्त आई०पी०एम० साहब ने चीफ इंजीनियर को इस बारे में चेंज करने के लिये मुकर्रर किया था। उन्होंने वह रिपोर्ट सैब्रटीज को की थी। एक डिमांड को छोड़ कर बाकी डिमांडज सैक्रेटरी लैवल पर नहीं मानी गई। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक डिप्टी सैक्रेटरी को ले लीजिये, सैक्रेटरीएट में वह एक छोटे से कमरे में बैठा होता है लेकिन जब उसे किसी कारपोरेट का चेयरमैन बना दिया जाए

तो वह बहुत बड़े कमरे में बैठता है और उसको और भी बहुत सुविधायें होती हैं इसलिये उनके वेतनमान गवर्नमेंट के साथ नहीं मिल सकते ।

**श्रीमती भांति देवी:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहले जवाब से स्वीकार किया है वह बात उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह वास्तव में सत्य था कि बर्गर सोचे समझे वह कमेटी बना दी गई?

**श्री लछमन सिंह:** स्पीकर साहब, वह कमेटी नहीं थी, वह तो दरअसल रिप्रेजेंटेटिव इन दी गई थी। उसको डिस्पाजे आफ करने के लिये वह मामला उनके सुपुर्द कर दिया था।

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):** स्पीकर साहब, कल परसों भी यह सवाल आया था और उस दिन भी मैंने इस बारे में क्लैरीफिकेटिव इन दी थी कि कोई कमेटी कांस्टीच्यूट नहीं की थी। जब कोई कमेटी कांस्टीच्यूट होती है तो उसका बाकायदा नोटिफिकेटिव इन होता है और भी फारमैलेटीज पूरी करनी होती है। यह तो उन्होंने सुझाव दिये थे ओर एक सुझाव के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एलान कर दिया है और बाकी जो सुझाव हैं उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अब तक कोई इनफरमेंट इन नहीं आई है कि वह सुझाव उनके मान लिये गये हैं या नहीं।

**श्री मूलचन्द मंगला:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि अभी तक जो सुझाव नहीं आये है, उन सुझावों को आने में कितनी देर लगेगी?

**श्री अध्यक्ष:** यह कोई सवाल नहीं बनता।

**श्रीमती भांति देवी:** अध्यक्ष महोदय, अभी सरदार लछमन सिंह जी ने स्वीकार किया कि तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी लेकिन चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कोई कमेटी नहीं बनी। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि इनमें से कौन सी बात सही है?

**श्री अध्यक्ष:** यह आपके समझने में अन्तर है।

**श्री फतेहचन्द विज:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने सवाल के जवाब में यह कहा कि वह मामला कमेटी को सौंपा गया और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने का कि कोई कमेटी नहीं बनी तो इनमें से कौन सी बात सच है?

**श्री अध्यक्ष:** आई०पी०एम० साहब इस बात को क्लैरीफाई कर चुके हैं। कहने के लिये चाहे आप उसे कमेटी कहें लेकिन असल में वह एक वर्किंग ग्रुप या स्टडी ग्रुप था। ऐसा ग्रुप किसी मसले पर अपना सुझाव दे सकता है लेकिन कमेटी बनाने के लिये बाकायदा नोटिफिके ान होती है। इसलिये यह कमेटी नहीं थी वह एक किस्म का वर्किंग ग्रुप या स्टडी ग्रुप था।

**श्रीमती भांति देवी:** स्पीकर साहब, इन्होंने सदन में कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी बनी है (व्यवधान)

**श्री लछमन सिंह:** मैंने यह नहीं कहा था, मैंने कहा था कि चीफ इंजीनियर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जो फार डिस्पोजी इनके पास भेज दिया था.....(व्यवधान)

**श्री दीपचन्द भाटिया:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जब वे बात करते हैं तो गैर-जिम्मेदाराना बात करते हैं (व्यवधान) पहले इनकी स्टेटमेंट और थी, अब और है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कागजात को देख कर बताया करे।

**श्री अध्यक्ष:** मिनिस्टर को यह कहना कि गैर-जिम्मेदाराना बात करते हैं, यह आपको भाभा नहीं देता।(व्यवधान)

**डा० बृज मोहन गुप्ता:** स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में पे-स्केल की डिस्पैरिटी रिमूव करने के लिये सवाल पूछा था लेकिन इन्होंने इसके जवाब में कह दिया ' नहीं'। मैं जानना चाहता हूँ कि पी.डब्ल्यू०डी० और इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में जो डिस्पैरिटी है, इसको दूर न करने के क्या कारण हैं यानि "नहीं" कहने का क्या कारण है?

**श्री अध्यक्ष:** इसका कारण जवाब के अन्दर दे रखा है (व्यवधान) क्या आपका यह मतलब है कि ट्रेसर, ड्राफ्टसमैन, हैड-ड्राफ्टसमैन, इन सब की बराबर पे होनी चाहिये?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इन सब की जाब ही मुखतलिफ है। (व्यवधान)

डा० बृज मोहन: मुखतलिफ नहीं है, एक ही स्टेट है, एक ही काम है लेकिन स्केल मुखतलिफ है, आप इस पर फिर से विचार करें। (व्यवधान)

श्रीमती भांति देवी: स्पीकर साहब, यह बडा इम्पोर्टेंट मामला है (व्यवधान)

**Loans written off by the Haryana Financial Corporation**

**\*1201 Master Jogi Ram:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the total amount of loans including that of the interest written off by the Haryana Financial Corporation since its inception to-date; and

(b) the names of the parties from whom the said amount was due in each case togetherwith the reasons for which the amounts were written off?

उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन):

(क) भून्य।

(ख) प्र न हीं नहीं उठता।

**श्री फतेहचन्द विज:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि हरियाणा फाइनें ाल कारपोरे ान का कोई लोन राईट-आफ नहीं किया है। क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इंडस्ट्रीज वालों को जो लोन देते है, उस सब की वसूली हो गई है?

**डा० मंगल सैन:** मैंने यह नहीं कहा कि सारा लोन वापिस हो गया है। स्पीकर साहब, इन्होने पूछा था कि क्या कोई लोन या इन्ट्रैस्ट राईट-आफ कर दिया गया है? मैंने कहा "नहीं"।

**श्री अध्यक्ष:** आउटस्टैंडिंग लोन हो सकता है लेकिन राईट आफ नहीं हुआ है।

**श्री मूलचन्द मंगला:** स्पीकर साहब, फाइनें ाल कारपोरे ान की तरफ से हिसार के कुछ हरिजनों को लोन दिया गया था लेकिन यह रूपया हरिजन लोगों को न मिल कर गुलाब सिंह जैन नाम का आदमी खा गया। इसमें बहुत घपला हैं इन गरीबों का लाखों रूपया खा गया हे, बीच में बडी हेराफेरी हुई है। क्या मंत्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करवायेगे?

**डा० मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूं कि मुझ से सवाल पूछा गया था कि कोइ लोन राईट आफ तो नहीं किया या कोइ इन्ट्रैस्ट राईट आफ तो नहीं किया गया हैं मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ही नहीं किये। जो घपले की बात बताई कि किसी

महानुभाव ने गोलमाल कर लिया, इस महानुभाव को, जिसने घपला किया है, मुआफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

**सरदार सुखदेव सिंह:** स्पीकर साहब, किसान की तरफ अगर 5 रूपये भी हो तो भी वसूल कर लिये जाते हैं लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से वसूली नहीं की जाती और फैक्ट्रियों वालों से वसूली का ढंग बड़ा गलत है। क्या सरकार इस ढंग को सुधारने की कोशिश करेगी?

**डा० मंगल सैन:** मेरे माननीय सदस्य ने बड़े काम का सवाल पूछा है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि हम वसूली के तरीके को बदलने पर विचार कर रहे हैं। जब किसान लगान, तकावी नहीं देता तो उसकी रिकवीर एज लैंड रैवेन्यु वसूल की जाती है। हम विचार कर रहे हैं कि पूंजीपतियों से भी इसी प्रकार का तरीका निकाल कर वसूली की जाये, जेल में ठोका जाये और पैसे की वसूली की जाये। (तालियां)

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** मंत्री महोदय ने बताया कि लोन और इन्ड्रैस्ट राईट आफ नहीं किया गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता कि गवर्नमेंट लैवल पर किसी डिपार्टमेंट में या कारपोरेट्स में राईट आफ करने के जो कागजात चल रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार है?



**डा० मंगल सैन:** मैंने साफ भावों में कहा है कि कोई राईट आफ नहीं किया गया। अब ये कह रहे कि कागजात चल रहे हैं कागजात चलने की बात मैंने गौर से नहीं देखी। अगर चल रहे होंगे तो राईट आफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

**श्री सुमेरचन्द भट्ट:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब से फाइनेंशियल कारपोरेट बननी है, तब से कितना अमाउंट डिफाल्ट में है, उस पर कितना इन्ड्रस्ट लगा है और कितने असेंसें डिफाल्ट में चल रहा है? इस रूपये को रिक्वर करने के लिये हकूमत ने क्या क्या कदम उठाये हैं?

**डा० मंगल सैन:** इस सवाल के लिये सैपरेट नोटिस चाहिये, लेकिन मैं माननीय सदस्य के सन्तोश के लिये और सदन की सूचना के लिये बताना चाहता हूँ कि जो रूपया डिफाल्ट में चल रहा है, हम उसको रिक्वर करने की पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ मुकदमें अदालत में गये हैं, वहां पर देरी लग रही है। इसलिये पहले जो मैंने रैमेडी बताई है कि जैसे किसानों से एजलैंड रैवेन्यु वसूल किया जाता है। उसी प्रकार का कोई माध्यम अपनाना चाहते हैं।

**श्री मांगें राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, हिसार में 'गुरुजी' नाम की एक फैक्टरी थी। उसने फाइनेंशियल कारपोरेट से 6 लाख रूपया लिया था लेकिन न तो हरियाणा में उस फैक्टरी की कोई प्रौपर्टी, न उसका कोई गारंटर है और न ही वह फैक्टरी

कहीं एग्जिस्ट करती है। क्या मंत्री महोदय इस 6 लाख रुपये की वसूली के बारे में बतायेंगे कि किस तरह से की जायेगी?

**डा० मंगल सैन:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने अभी गुरु-दिश्य की बात कही। जनता सरकार के भासनकाल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन पहली सरकार ने जो गुनाह किये है, उनके बारे में मैं देख लूंगा ओर जो उचित कार्यवाही होगी, जरूर की जाएगी।

**चौधरी लाल सिंह:** स्पीकर साहब, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मूलचन्द मंगला ने सवाल पूछा था कि हरिजनों के नाम पर, हिसार का एक बहुत बडा आदमी पैसा खा गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से जो हरिजनों को लूटते है, हरिजनों को बचाया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष:** इसका जवाब आ चुका है।

**चौधरी संत कंवर:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि फाइनें ल कारपोरे न द्वारा फ्री आफ इन्ट्रैस्ट लोन दिया जाता है? अगर दिया जाता है तो इस में किस-किस कैटेगरी के लोग आते है?

**डा०मंगल सैन:** स्पीकर साहब, फाइनें ल कारपोर न, एक प्रकार का बैंकिग इन्स्टीच्यु न है, इसका वाणिज्य का धंध है, सूद के बिना तो यह बात ही नहीं करता। इसलिये किसी को बिना सूद के लोन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

**श्री फतेहचन्द विज:** स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्टर्ज ने 1962 में चाईना के साथ हुई लडाई में और 1965 मे पाकिस्तान के साथ हुई लडाई में दे ा की रक्षा करने में बढचढ कर हिस्सा लिया, लेकिन इनको लोन देनार सरकार ने बन्द कर दिया। क्या मंत्री महोदय दोबारा लोन देने की स्कीम पर सोच रहे है ताकि इस क्लास को भी लोन की फ़ैसिलिटी मिल सके?

**डा० मंगल सैन:** ट्रांसपोर्टर्ज को रूपया देकर फाइनें ाल कारपोरे ान को रूपया रीयलाइज करने में बडी दिक्कत आती थी। ट्रक ओर या ट्रक ड्राईवर दे ा भर में औप्रेट करते हे, इसी कारण से यह रूपया वसूल नहीं होता था। इस कठिनाईयों को देखते हुये फाइनें ाल कारपोरे ान ने इनको रूपया देना बन्द कर दिया था। जंहा तक नये सिरे से विचार करने का सवाल है, इस पर विचार किया जा सकता है।

**चौधरी जगजीत सिंह पोहलू:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि जिस तरह से किसान और मजदूर से लैंड रैवेन्यू के तौर पर कर्जा वसूल किया जाता है उसी तरहसे पूंजीपतियों से कर्जा वसूल करने के लिये सरकार विचार कर रही है। क्या मंत्री जी बतायेगें कि कब तक फ़ैसला कर लेगें क्योंकि जनता सरकार को दो साल तो बने हुये हो गये है?

**डा० मंगल सैन:** जितनी जल्दी हो सकेगा करेगें।

## **Yoga Centres in the State**

**\*928. Swami Adityvesh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether any Yoga Centre has been opened during the period from the 4<sup>th</sup> July, 1977 to 30<sup>th</sup> June, 1978 in the State; and

(b) if so, the name of place where it has been opened together with the type of Education being imparted there?

**शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):**

(अ) नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

**स्वामी आदित्यवेश:** मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि योग केन्द्र क्यों नहीं खोले गये?

**श्री हीरानन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, 1997 में 11 आसामियों की सिलैबान के लिये एस0एस0एस0 बोर्ड के पास रिक्वीजिटान भेजी गई थी लेकिन केवल तीन की सिलैबान की गई। मैं समझता हूँ कि योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी होगी।

**चौधरी हर स्वरूप बूरा:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर कुल कितने योग केन्द्र हैं?

**श्री हीरानन्द आर्य:** इस समय चार केन्द्र कार्य कर रहे हैं?

**डा० बृज मोहन गुप्ता:** क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरियाणा के अन्दर महिलाओं और पुरुषों के लिये अलग-अलग योग सेंटर है या इकट्ठे हैं?

**श्री हीरानन्द आर्य:** इसके बारे में मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं। जमुनानगर में दोनों प्रकार के केन्द्र हैं। टाईमिंग का मुझे पता नहीं है कि उनकी क्लासिज एक ही समय में चलती हैं या अलग अलग समय में चलती हैं।

**चौधरी देस राज:** क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चण्डीगढ़ में एम०एल०एज० और मिनिस्टर्स के लिये कोई योग सेंटर खोलने की तजवीज है? (हंसी)

**श्री अध्यक्ष:** मेरे ख्याल में मंत्रियों और एम०एल०एज० के स्वास्थ्य के लिये सुझाव तो अच्छी है। (हंसी)

**श्री हीरानन्द आर्य:** सुझाव तो अच्छा है लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनियन टैरेटरी होने के नाते से भाग्यद यहाँ हमें ऐसा सेंटर खोल न सकें। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** इसके लिये तो मैं विधान सभा में एक कममरा मुहैया कर सकता हूँ।

**चौधरी खुर गद अहमद:** स्पीकर साहब, आपने तो बडी मेहरबानी की जो विधान सभा में कमरा देने के लिये तैयार हो गये लेकिन क्या मंत्री जी स्वामी जी की औनरेरी सर्विसजि लेकर इस योग सैन्टर को यहां भुरु करेगें? (हंसी)

**श्री हीरानन्द आर्य:** ये अगर दरख्वास्त देगें तो जरूर भुरु करेगें ।

**चौधरी हरिचन्द हुड्डा:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि रोहतक के अन्दर 4 योग सैन्टर चल रहे है । क्या वे बतायेंगें कि इनको कब तक बन्द करेगें अगर ये योग केन्द्र मौरल करैक्टर पर धब्बा हों? (विधान) स्पीकर साहब,—

न भादी न सांदा,

न रंज पर भाोग,

इसी का नाम है योग ।

**श्री अध्यक्ष:** यह आपका सुझाव है या सवाल है?

**चौधरी हरिचन्द हुड्डा:** स्पीकर साहब, ऐसा है कि सुझाव और सवाल दोनों ही है । कहने का मतलब यह कि अगर क्लीयर चीज हाउस के सामने आ जाए तो लोगों का भला हो सकता है ।

**श्री हीरानन्द आर्यः** अध्यक्ष महोदय, रोहतक में हमने कोई योग केंद्र नहीं खोला है इन्होंने खोल रखे हो तो वे मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** मैं भी हैरान था। आपने यह तो कहा था कि चार योग केंद्र है लेकिन रोहतक का नाम नहीं लिया था।

**डा० बृज मोहन गुप्ता:** स्पीकर साहब, जमुनानगर का योग सेंटर ऐसा है जहां महिलायें भी है और पुरुश भी है। पिछले दिनों वहां दुराचार का एक केस हुआ था और दोवी रैड हैंडिड पकडा गया था। क्या मंत्री जी बतायेगें कि महिलाओं के लिये अलग और पुरुशों के लिये अलग सेंटर खोले जायेगें और साथ ही महिला योग केंद्र में महिला प्रििक्षक तथा पुरुश योग केंद्र में पुरुश प्रििक्षक लगाने का विचार करेगें?

**श्री हीरानन्द आर्यः** अध्यक्ष महोदय, केस के सम्बन्ध में तो इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन अगर कहीं से ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में आयेगी कि फंला जगह योग सीखने वाली लडकियों की संख्या काफी है तो वहां के लिये महिला योग प्रििक्षक लगाने पर विचार यिका जा सकता है।

**स्वामी आदित्यवे 1:** क्या मंत्री जी बतायेगें कि जो चार योग केंद्र खुले हुये है उनमें रजनी 1 टाईप या महे 1 योगी टाईप कौनर सा योग सिखाया जाता है?

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, इसके लिये अलहिदा नोटिस चाहिये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोग आदरणीय रजनी 1 के आश्रम से सर्टिफिकेट लेकर आए हों उन लोगों को इन योग केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के लिये लगाया जाएगा?

श्री हीरानन्द आर्य: आपके पास यदि सर्टिफिकेट हो तो आपको हम जरूर रिक्रूट करेंगे।

**Enquiry against Improvement Trust Jagadhri**

\*1200 .Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether any enquiry is pending regarding the duplicate Measurement Book in connection with the building of Improvement Trust Jagadhri; and

(b) if so, to whom the enquiry has been entrusted or is proposed to be entrusted?

स्थानीय भासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा):

(ए) हां।

(बी) जाचं चौकसी विभाग द्वारा की जा रही है।



**डा० बृज मोहन गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या चौकसी विभाग से ये इंकवायरी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेगा?

**चौधरी राम लाल वधवा:** अध्यक्ष महोदय, यह केस जगाधरी के श्री पी०के० गोयल, चेयरमैन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, से संबंध रखने वाला केस है। ये कांग्रेस राज के वक्त चेयरमैन बन गये थे इनके अगेंसट 6-6-77 को मुख्य मंत्री जी के पास एक कम्प्लेन्ट आई थी। 13-6-77 को उन्होंने इसे डिपार्टमेंट के पास भेजा था हमने 18-7-77 को इसे डिप्टी कमि नर के पास इंकवायरी के लिये भेज दिया। 16-11-77 को यह वहां से वापस आई। उसके बाद इसे हमने चौकसी विभाग को भेज दिया। चौकसी विभाग ने उस पर अम्बाला चौकसी विभाग को आर्डर किये कि वह इस बारे में छानबीन करे। 13-1-78 को वह रिपोर्ट वहां से आई थी। लेकिन उसके कुछ प्वायंट पर कलैरिफिके टन मांगी गई है। उनको यह भी कहा है कि वे भीघ रिपोर्ट भेजें इसको हम ऐक्सपीडाइट कर रहे हैं।

**सरदार सुखदेव सिंह:** स्पीकर साहब, कांग्रेस राज में डबवाली के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भी गबन हुआ था। उसकी इंकवायरी भी विजिलैन्स डिपार्टमेंट कर रहा था। क्या मंत्री जी बतायेगे कि उसकी क्या पोजी टन है?

**चौधरी राम लाल वधवा:** मेरे नोटिस में यह बात नहीं है अगर माननीय सदस्य इसके लिये नोटिस देंगे तो जवाब दे दूंगा या ये मुझे मेरे आफिस में मिल ले। इन्हें उसकी पोजि न बता दूंगा।

**श्री सुमेर चन्द भट्ट:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह किस किस्म की रिपोर्ट थी?

**श्री अध्यक्ष:** पहले मंत्री महोदय यह बताये कि मैयरमेंट बुक क्या होती है?

**चौधरी राम लाल वधवा:** कान्ट्रैक्टर जो भी काम करता है वह एक किताब में दर्ज होता है उसको एम0बी0 कहते हैं रिपोर्ट इस तरह की है कि कान्ट्रैक्टर चेयरमैन के साथ मिल लिया और एम0बी0 को बदल कर नई एम0बी0 लगा कर उसको नाजायज तोर पर फायदा पहुंचाना चाहता था।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा:** क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जिस चेयरमैन , इमप्रूवमेंट ट्रस्ट , के खिलाफ इन्कवायरी की जा रही है उसमें कान्ट्रैक्टर भी शामिल है?

**चौधरी राम लाल वधवा:** कम्प्लेन्ट अध्यक्ष के खिलाफ हैं वह चौकसी विभाग के भेजी हुई है। रिपोर्ट आने पर पता चलेगा

कि अया उसमें कान्ट्रैक्टर भी शामिल है या नहीं। जो भी इनवाल्ड होगा उसके खिलाफ ऐव इन लिया जायेगा।

**श्री दीपचन्द भाटिया:** स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने जवाब दिया है कि दो सल से यानि 6-6-77 से चेयरमैन के खिलाफ कम्पलैन्ट दर्ज की हुई है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हं कि क्या पांच साल में इन्क्वायरी पूरी हो जायेगी?

**चौधरी राम लाल वधवा:** पांच साल की बात तो बहुत दूर है। मैं इस अप्रैल तक कोर्ट में करूंगा कि विजिलैन्स डिपार्टमेंट से इन्क्वायरी पूरा हो कर आ जाये।

**श्री भलेराम:** स्पीकर साहब, मे मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पीछे जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तोड़े गये थे वे इन्क्वायरी होने की वजह से तोड़े गये थे या कोई और कारण था?

**चौधरी राम लाल वधवा:** वैसे तो इस सप्लीमेंटरी का इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है लेकिन जनता सरकार ने जो चेयरमेन बनाये थे उनके खिलाफ कोई रिक्वायत नहीं थी।

**चौधरी जगजीत सिंह पोहलू:** स्पीकर साहब, जनता सरकार ने जिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस को तोडा था क्याउनमें फिर से नये चेयरमेन बनाने की प्रोपोजल है?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का मूल प्र न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**Shri Surrender Singh:** This is a matter of policy.

**Mr. Speaker:** It has got no connection with the main question.

**Shri Surrender Singh:** I so concede that. But the Minister is supposed to know the policy of the Government.

**Mr. Speaker:** I do not see the relevance of it. The question is very specific as to whether any enquiry is pending regarding the duplicate measurement book in connection with the building of Improvement Trust Jagadhri-----

**Shri Surrender Singh:** This is a policy matter and the Minister is supposed to know the policy.

**Mr. Speaker:** It is a policy matter and supplementary cannot be asked on a matter of policy. It should be relevant to the main question.

श्री सुरेन्द्र सिंह: लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि इन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स में बड़ी धांधली मची हुई है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग सवाल है। अगर आप नोटिस देंगे तो उसे मैं अव य एडमिट करूंगा। लेकिन आप सभी इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के बारे में पूछ रहे हैं जब कि सवाल केवल जगाधरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का है। (विघ्न)

**चौधरी राम लाल वधवा:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कनफयुजन खत्म कर देता हूँ। हमारे रिजिम में बनाये गये चेयरमैनो के खिलाफ किसी किस्म की रिक्वायत नहीं है। अगर आप पुछना ही चाहते है तो करनाल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सुरजीत सिंह मान और जगाधरी के चेयरमैन के खिलाफ रिक्वायतें दर्ज हैं, जो कांग्रेस राज के टाईम में थे।

**श्री अध्यक्ष:** मैं मैबर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि सप्लीमेंटरी का सम्बन्ध डायरेक्टली मेन क्वै चन से होना चाहिये। जो सप्लीमेंटरी मेन क्वै चन से सम्बन्धित नहीं होगा उसके बारे में मुझे खेद है, मैं उसे अलाउ नहीं करूंगा।

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये मिनिस्टर महोदय से जानना चाहती हूँ कि जब जनता सरकार में किसी चेयरमैन के खिलाफ कोई रिक्वायत हीं नहीं थी तो फिर इनको क्यों हटाया गया? (विघन)

(इस प्रान का उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री फतेह चन्द विज:** मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि जगाधरी इम्प्रूवमेंट के चेयरमैन के खिलाफ दो साल से इन्क्वायरी पेंडिंग है, क्या इस बारे में चौकसी विभाग को रिमाइन्डर वगैरह दिया गया है कि इन्क्वायरी रिपोर्ट जल्दी भेजे।

**श्री अध्यक्ष:** रिमाइन्डर्ज के बारे में यहां पर पूछना उचित नहीं है।

**श्री गुलजार सिंह:** मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि हजस सतरह से जगाधरी के अन्दर गबन हुआ है उसी तरह से करनारल में भी हुआ है क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर जिसने गबन किया है उसके खिलाफ क्या कुछ ऐव न लिया जा रहा है?

**श्री अध्यक्ष:** इस सवाल का मेन क्वै चन से कोइ सम्बन्ध नहीं है।

**डा० बृज मोहन गुप्ता:** स्पीकर साहब, जगाधरी में दो मार्किटस बनायी गई है। एक मार्किट का नाम इन्दिरा मार्किट है और दूसरी का नाम बंसी लाल मार्किट है। अभी इन दोनों के नाम नहीं बदले हैं दूसरे इन्दिरा मार्किट तो बन चुकी है लेकिन बंसी लाल मार्किट आज भी अधूरी पडी है तो मैं जानना चाहता कि वह कब तक कम्पलीट हो जायेगी?

**चौधरी राम लाल वधवा:** जो अधूरी पडी है उसे भी पूरा करेगे।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा:** क्या मिनिस्टर महोदय बतायेंगे कि कितने हजार के गबन की इन्क्वायरी है?

**चौधरी राम लाल वधवा:** चौकसी विभाग से रिपोर्ट आने के प चात पला लगेगा कि कितना अमाउन्ट इन्वाल्वड है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: क्या सरकार इम्प्रवमेंट ट्रस्टस के चेयरमैन दुबारा बनायेगी?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मेंबरज , आज केवल पांच सवाल थे जो अब खत्म हो गये है। ऐसा लगता है कि आज मेंबर साहिबान की काफी सन्तुष्टि हो गई होगी।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

**Air-Trips by Principal Secretary to the Chief Minister**

**281. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of air-trips outside and inside the Haryana State which have been undertaken by the Principal Secretary to the Chief Minister after the formation of Janata Party Government;

(b) the number of air-tirps out of those referred to in part (a) above undertaken fro official and private pruposes, separately; and

(c) the total expenditure incurred by Government on the said air-trips?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

(क), (ख) और (ग) : इन यात्राओं / वापसी यात्राओं की संख्या पांच है। इन में मुख्य मंत्री के साथ की गई यात्रायें भामिल नहीं है। यह यात्राएं सरकारी कार्यों के लिये की गई और इस अधिकारी के लिये हवाई यात्राओं का खर्चा 5692 रुपये 55 पैसे हुआ।

### ध्यानाकर्षण सूचनायें

#### 1. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अभिकथित कार्यवाहियों सम्बन्धी

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, मैने कल भाम को एक काल अटैन ान मो ान दी थी।

श्री अध्यक्ष: आपने तो तीन चार काल-अटैन ान मो ान दी हुई हैं आप किसके बारे में पता करना चाहते हैं?

श्री भाम ार सिंह: एक व्हीट प्राईस के बारे में है.....  
.....

श्री अध्यक्ष: आपने जो काल अटैन ान मो ान दिया था, I have disallowed that. If you want to know the reasons, I can read them out. जो आपका काल अटैन ान मो ान किसी पोलिटीकल पार्टी, पोलिटीकल आग्रेनाईजे ान या सैमी-पोलिटीकल आग्रेनाईजे ान के सम्बन्ध में था, वह इन ग़रउन्डज पर डिस अलाउ किया गया है।



One of the provisions in the Constitution is of "Equality before Law." It says "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of land". There is also provision about protection of certain rights regarding freedom of speech etc. which says-

(1) all citizens shall have the right-

(a) to freedom of speech and expression.

(b) to assemble peaceably and without arms;

(c) to form association or unions;

etc.etc.

In the light of these specific provision guaranteed under the constitution, I have not allowed the call attention notice that has been given by you.

**Shri Shamsheer Singh:** You have not referred the subject matter of the call attention motion.

**श्री अध्यक्ष:** काल अटैन् इन मो इन जो इन्होने दिया था, उसका सब्जैक्ट मैटर यह था कि नागपुर मे एक मीटिंग हुई थी, उसमें आर०एस०एस० की कुछ आलोचना की गयी थी, उसके बारे में इन्होने काल अटैन् इन मो इन दिया था। मैं यह समझता हूं कि आर०एस०एस० के बारे में, यानि किसी भी पोलिटीकल पार्टी या सैमी पोलिटिकल आर्गेनाईजे इन के बारे में हाउस में काल

अटैन्डान्स मोडल एडमिट करना उचित नहीं है, इसिलिये मैने उसको डिस्-अलाउ कर दिया है।

**श्री भामदेव सिंह:** स्पीकर साहब, मैने नागपुर के बारे में तो नहीं दिया था, मैने तो हरियाणा के बारे में दिया था कि हरियाणा के मुखतलिफ डिपार्टमेंट में, युनिवर्सिटीज में, स्कूलों और कालेजिज में आर०एस०एसव० के लोग भर्ती हो रहे हैं। मैने नागपुर के बारे में कोई काल अटैन्डान्स नहीं दिया था।

**उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन):** अध्यक्ष महोदय, काल अटैन्डान्स में, अगर कोई इम्पीजीयेट या अरजैन्ट मामला हो, तो गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने का एक जरिया है। इस तरह से थोड़े किया जा सकता है, जिस तरह से ये कर रहे हैं। इनको तो आर०एस०एस० का फोबिया हो गया है।

**Mr. Speaker:** That has been disallowed.

**चौधरी संत कवर:** स्पीकर साहब, कमन्स तो ये खुद है लेकिन कह रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस के हरियाणा के वाइस प्रेजिडेंट पंडित चिरंजी लाल भार्मा ने एक ब्राह्मणों के जाटों के खिलाफ मोर्चा बनाना है।

**श्री अध्यक्ष:** चौधरी संत कवर, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस समय जो काल अटैन्डान्स हाउस के सामने है, वह रिजैक्ट हो चुका है। इस पर फरदर डिस्कशन नहीं हो सकती।

श्री भाम रे सिंह: यहां पर यह कहा गया है.....  
.....। (व्यवधान तथा  
भोर)

**Mr. Speaker:** Nothing regarding this call attention motion, except my ruling that it has been disallowed for the reasons given, be recorded.

श्री भाम रे सिंह: .....

2. कृषि उपज की कम कीमतों तथा कृषि इन-पुटस तथा कंज्युमर गुडज की चढ़ती हुई कीमतों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: एक और काल अटैन् इन मो इन श्री भाम रे सिंह सुरजेवाला तथा कुछ और महानुभावों की तरफ से था Concerning the low agricultural prices and ever soaring prices of inputs and consumer goods. I have disallowed it because this matter has already been discussed in the House and the Minister concerned made a statement in the House on the 16<sup>th</sup> March, 1979, in respect of support price of wheat etc. सदन को याद होगा कि श्री हर स्वरूप बूरा का एक काल अटैन् इन मो इन पौटैटो तथा दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोड्युसिज की प्राईस के बारे में था जिसके उपर मंत्री महोदय ने 16 मार्च को कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद आगे और कोई डिक्लैरमेंट नहीं हुई है। इसलिये मैंने यह काल अटैन् इन मो इन डिस्अलाउ कर दिया है।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर प्राईस कमी ान ने व्हीट की प्राईस 115 रूपये प्रति क्विंटल रिकमेंड की है। हम जानना चाहते कि सरकार उसके बारे में क्या कर रही है या करना चाहती है क्योंकि हरियाणा में व्हीट की प्रोडक् ान प्राईस इससे कहीं ज्यादा है। (व्यवधान एंव भाोर)

**Mr. Speaker:** That is outside the purview of this House.

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, पहले इस बारे में कोई काल अटैन् ान मो ान नहीं आयी थी और न ही मंत्री महोदय ने जवाब दिया है क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर प्राईस कमी ान की रिपोर्ट भी नहीं आयी थी। यह काल अटैन् ान मो ान सिर्फ व्हीट प्राईस के बारे में है जो कमी ान ने 115 रूपये रिकमेंड की है।

**Mr. Speaker:** If you want to say anything about the ruling, you may kindly meet me in my Chamber and discuss it with me. But for the present my decision stands that the call attention motion is disallowed.

3. पंजाब स्टेट री-आर्गेनाइजे ान एक्ट, 1966 के अधीन कारपोरेट बौडीज में हरियाणा के हिस्से सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: एक और काल अटैन् ान मो ान श्री भाम ार सिंह सुरजेवाला की तरफ से आयी थी जो पंजाब स्टेट री-आर्गेनाइजे ान एक्ट 1966 के सैक् ान 72 के तहत कारपोरेट

बोडीज यानि पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ के बंटवारे के बारे में थी।.....

**श्री भाम रेर सिंह:** स्पीकर साहब, डिवीजन के बारे में तो नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष:** एक्ट के तहत हरियाणा को जो 40 प्रति त भोयर इन बोडीज में मिला था, उसके सम्बन्ध में है।

**श्री भाम रेर सिंह:** डिवीजन का भाब्द कहीं नहीं है। इन बोडीज में हरियाणा का भोयर लेने के बारे में है।

**श्री अध्यक्ष:** यह इन वजूहात की बिना पर डिसअलाउ कर दिया गया है:

(a) It raises more than one matter.

(b) It does not fall within the responsibility of the State Government.

(c) It is not a matter of recent occurrence.

रीसैन्ट अकरेंस वह होता है जो हाल ही में हुआ हो लेकिन इस एक्ट को लागू हुये तो 10-15 साल से ज्यादा हो गये है। यह रीसैन्ट अकरेंस का मामला नहीं है।

(d) It relates to an autonomous/statutory body and its day-to-day internal administrative matters.

**श्री सुरेन्द्र सिंह:** आपने कहा है कि यह एक से ज्यादा मैटर्ज को डील करता है। मेरी अर्ज यह है कि इसमें तो एक ही मैअर है कि इन बौडीज में हरियाणा का पुरा भोयर होना चाहिये जो एक्ट के तहत 40 प्रति त नि चित किया गया है।

**श्री अध्यक्ष:** इसमें भाशण देने की गुजाइं नही है।  
My ruling is quite clear and there can be no discussion on it.

**Shri Surrender Singh:** I am only submitting to the House that if should recommend to the Central Government.....

**Mr. Speaker:** You cannot discuss that call attention motion. I have given my ruling and there can be no discussion on it. If you want to say anything on my ruling. You kindly see me in my Chamber;

**श्री भाम ेर सिंह:** स्पीकर साहब, फाजिल्का और अबोहर में पजांबी कम्पलसरी पढाई जा रही है जिससे हरियाणा को काफी नुकसान होगा तथा पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा का पूरा भोयर नहीं मिल रहा है....  
.....।

**श्री अध्यक्ष:** मेरी रूलिंग फाईनल है तथा इस पर हाउस में कोई डिसकूशन नहीं हो सकती। अगर आपने कुछ कहना है तो आप बड़ी खुशी से मेरे चैम्बर में मिल सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं।

**Mr. Speaker:** Now the Chairman of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will present the report of the Committee.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।  
स्पीकर साहब, मैनें हरियाणा में.....  
.....

श्री अध्यक्ष: यह बात खत्म हो चुकी है। आप बैठिये। I  
will not allow any discussion on my ruling.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: .....  
....(विघ्न)

**Mr. Speaker:** I have quoted the rule that anything relating to any political organization or semi-political organization cannot be discussed on the floor of the House.  
(Interruptions)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : .....  
..... आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

**Mr. Speaker:** Your point of order is disallowed.  
Please sit down.

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आपने एक रूलिंग दे दी और मैं न डिसअलाउ कर दी। उसके बाद ये बार-बार खड़े होकर एक पार्टी का नाम लेकर खामखाह एक बात को उछालने की कोशिश कर

रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो इन्होंने कहा है वह हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

**Mr. Speaker:** I think, the House had sufficient time to blow nout hot air. Now I would request that some semblance of order and discipline should be restored.

**मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):** स्पीकर साहब, जिस हिसाब से ये लोग हाउस की कार्यवाही में दखल दे रहे हैं यह ठीक नहीं है। ये लोग वाक आउट तो करना चाहते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि आप इन्हें नेम कर दें ताकि इनका नाम अखबारों में आ जाये। आप इनके साथ रियायती बर्ताव कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना भाोर कर रहे हैं।

**श्री भाम ेर सिंह:** जो लीडर आफ दि हाउस ने कहा है उस पर हम स्ट्रॉंगली प्रोटैस्ट करते हैं। We are speaking in the exercise of our right. Kindly listen to our view point-----

**श्री अध्यक्ष:** मैंने आपका कोई पवायंट आफ आर्डर डिसअलाउ नहीं किया है। आपको बोलने का पूरा मौका दिया हे लेकिन जब चार-पांच साहिबान इकट्ठे होकर बोलने लगे तो न मेरी समझ में कोई चीज आ सकती है और न ही हाउस की समझ में कोई चीज आ सकती है और हाउस के डिस्पलिन के लिहाज से भी यह ठीक नहीं है।

**श्री भाम ेर सिंह:** स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुन लीजिये।



**चौधरी देवी लाल:** स्पीकर की रूलिंग पर न तो कोई प्वायंट आफ आर्डर रेज किया जा सकता है। और न ही कोई डिस्कान की जा सकती है। (विधन)

**श्री अध्यक्ष:** जो मैंने काल अटैन्शन नोटिस पर रूलिंग दी है उस पर कोई प्वायंट आफ आर्डर रेज नहीं हो सकता है। मैं कोई रिजिड तरीके से काम नहीं करता। अगर आपने मेरी रूलिंग के बारे में कोई बात कहनी है तो आप कृपया बड़ी खुशी से मेरे चैम्बर में आकर मेरे से चाहे घंटों/दो घंटे डिस्कान कर सकते हैं। मैं आपका प्वायंट आफ व्यू सुनुंगा और उस पर पूरे तौर से विचार करूंगा लेकिन हाउस के अन्दर मेरी रूलिंग पर न कोई प्वायंट आफ आर्डर और न ही डिस्कान अलाउ की जा सकती है। (भागेर)

**श्री भामदेर सिंह:** स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुन लीजिये।.....(विधन एवं भागेर)

**Mr. Speaker:** I am sorry, I have already given my ruling on the call attention notice. I will not entertain any point of order on my ruling. Your point of order is disallowed and nothing will be recorded.

**श्री भामदेर सिंह:** .....

.....

**Mr. Speaker:** If any hon. Member wants to discuss anything about my ruling, he may kindly come to my Chamber.

**श्री मांगे राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है कि मैंने 14 तारीख को हरियाणा से "गऊ निकास पर पाबन्दी" के बारे में एक रैजाल्यू इन भेजा था और छुट्टी होने की वजह से आपके दफतर में वह 17 तारीख को मिला। वह रैजाल्यू इन यह कह कर रिजैक्ट कर दिया गया चूंकि रैजाल्यू इन देने के लिय पन्द्रह दिन का नोटिस होना जरूरी है इसलिये 29 तारीख को यह लिस्ट पर नहीं आ सकता है लेकिन जो लिस्ट आज मैं देख रहा हूं। उसमें कल के दिये हुये रैजाल्यू इन आज की लिस्ट पर आ गये है जबकि मेरा रैजाल्यू इन पन्द्रह दिन न होने के कारण से रिजैक्ट कर दिया गया।

**श्री अध्यक्ष:** आप इस सम्बन्ध में मेरे से चैम्बर में मिलें। इस समय इस पर कोई बात करना हाउस का समय पश्ट करने वाली बात है।

**श्री भामोर सिंह:** स्पीकर साहब, आज के ऐजेन्डा पर मेरा रैजाल्यू इन है लेकिन आज की लिस्ट आफ बिजनैस न तो मुझे कल भाम को मिली ओर न ही आज सुबह दी गइ है यह मुझे डेलिब्रेटली नहीं भेजी गई है। आप इसकी पड़ताल करें।

**Mr. Speaker:** I will enquire into the matter.

**श्री देवेन्द्र भार्मा:** स्पीकर साहब, आप बडे लिबरल आदमी है भायद मिलिटरी में रहने के कारण लिबरल हो गये है। कल हमरे एक सीजन्ड ओर बुजुर्ग आदमी ने ने इनल करैक्टर बिल्डिंग की बात कही थी। यह कैसा करैक्टर बिल्डिंग है कि दस एम0एल0एज0 यहां खडे होकर भाोर करने लगते है। आप कम से कम एम0एल0एज0 के लिये रिस्ट्रिक् इन लगा दें कि एम0एल0ए0बनने से पहले उन्हे मिलिटरी की ट्रेनिंग लेनी चाहिये या एन0सी0सी0 की ट्रेनिंग लेनी चाहिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, यह बारबार एम0एल0एज0 को तजुर्बे ओर मिलिटरी की ट्रेनिंग की बात कह रहे है। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** इन्होने एक साइड के लिये नहीं कहा है सब के लिये कहा है।

**Shri Surrender Singh:** He exhibits his own character and needs proper training.

### वाक आउट

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुने। हमने तो स्टेट में आर0एस0एस0 की एक्टीवीटीज ( गोर एवं विधन)

**Mr. Speaker:** You are again raising an irrelevant point of order. Please take your seat.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है.....

श्री अध्यक्ष: मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी रूलिंग पर कोई प्वायंट आफ आर्डर रोज नहीं हो सकता। अगर आप इस विषय में कोई बात करना चाहते हो तो आप मेरे चैम्बर में आकर मेरे से बात कर सकते हो।

(इस समय अपोजी इन बैंचिज की तरफ से बहुत से सदस्य खड़े हुये)

**Mr. Speaker:** Order please. There can be no discussion on my ruling.

आवाजें: स्पीकर साहब, अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम इसका विरोध करते हुये वाक आउट करते हैं।

(इस समय सर्वश्री भामारे सिंह, बीरेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, दलीप सिंह, नारायण सिंह, जगजीत सिंह पोहलू, तथा मांगे राम गुप्ता सदन से उठ कर चले गये) ( ओर)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी अपोजी इन बैंचिज पर बैठते हैं उनका जितना हम बनता है वह मैं अपनी तरफ से दुगना देता हूँ यानि आजकल की हालत को देखते हुये मैं उनको बोलने के लिये दुगना टाईम देता हूँ ओर दुगनी सहूलियत देता हूँ लेकिन

मेरे को समझ नहीं आया कि वे किस बात पर वाक आउट कर गये हैं। अगर उन्होंने काल अटैन्-ान मो-ान पर मेरी रूलिंग के खिलाफ वाक आउट किया है तो यह बड़े अफसोस की बात है। मैं तो उनके साथ बड़ी नरमी बर्त रहा हूँ फिर भी वे ऐसा कर रहे हैं?

**मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल):** स्पीकर साहब, मैंने तो यह पहले ही कह दिया था कि ये ऐसी हालत पैदा करना चाहते हैं कि आप इनको नेम करें। अच्छा किया आपने इनको नेम नहीं किया और वे अपने आप चले गये।

**उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन):** स्पीकर साहब, कांग्रेस राज में हम भी इस सदन के सदस्य रहे और उस टाइम के स्पीकर साहब भी थे लेकिन जितना लिबरली और उदारता से आप इनको सुनते हैं यह लोकतन्त्र में आपने एक अच्छी मिसाल कायम की है। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। ये लोग इतना हुडदंग मचा रहे हैं लेकिन फिर भी आप इतने उदार हैं लेकिन उस समय जब हम बोलते थे तो उस समय के मुख्य मंत्री कह देते थे कि इसको अभी संस्पैड किया जाये। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हैं और आप भी बहुत उदार हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हमारी जनता पार्टी डैमोक्रेसी के सिद्धांतों को कायम रखने के लिये भी बधाई की पात्र है। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ कि इतनी बाधाओं के बावजूद भी आप योग्यता से हाउस का काम निभा रहे हैं।

**चौधरी लाल सिंह:** स्पीकर साहिब, आपकी इतनी भाराफत के बाद भी ये इस तरह से करते है। अब तक तो पिछली सरकार ने जनता को परे गान किया था और अब ये हाउस को परे गान कर रहे है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं इनका कोई पक्का इन्तजाम होना चाहिये।

**श्री देवेन्द्र भार्मा:** स्पीकर साहब, जब हम मीसा में बन्द थे तो वहां पर हमें सिवाये बीबीसी सुनने के ओर कुछ नहीं मिलता था। उस समय का मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक मिनिस्टर किसी सभा में बोल रहा था तो पीछे से किसी ने उसके उपर गुब्बारा फेंक दिया। तो उस मिनिस्टर ने पुलिस को बीच में नही आने दिया और कहा कि मैं गुब्बारा करने वाले से खुद बात कर लूंगा। उसने कहा कि असली डैमोकेसी यही हैं लेकिन स्पीकर साहब, आज जो हमने इनका डिस्प्लिन देखा इसके बारे में आपको कुछ करना चाहिये।

**स्थानीय भासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा):** स्पीकर साहब, मैं पिछली सरकार के टाईम को याद कर रहा हूं। उस टाईम प्वायंट आफ आर्डर मैं भी करता था लेकिन स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद, अगर मैं खड़ा हो जाता था तो पोसवाल साहब अब भी यहां मौजूद है इनसे पूछलो, उसी समय कह दिया जाता था कि इसको बाहर निकालने के कागज तैयार करे। लेकिन स्पीकर साहब, आपने डैमोकेसी को सही मायनों में लागू किया है। हाउस का डैकोरम कायम रखने के लिये उन लोगों को भी इस

पर विचार करना चाहिये और आप भी थोडा सा इस बारे में देखें कि हाउस का डिस्पिन कायम रहे। आप उनके साथ बहुत नमी बर्त रहे है लेकिन वे फिर ऐसा कर रहे है।

**कमेटी आन दि वैल्फेयर आफ रिडल्यूड कास्टस एंड रिड्यूल्ड ट्राइब्ज की चौथी रिपोर्ट पे पढना**

चौधरी गया लाल (चेयरमैन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति): स्पीकर साहब, मैं वर्ष 1978-79 के लिये हरियाणा विधान सभा की अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की चौथी रिपोर्ट (इसके अनुबन्ध सहित) की टाईप की हुई प्रति सदन में पे पढ करता हूँ।

**गैर-सरकारी प्रस्ताव**

1. राज्य में उच्च भारा प्र तासन में वृद्धि रोकने के लिये आई0एम0एस0 काडर की संख्या में और वृद्धि न करने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब 8 मार्च को श्री कंवल सिंह, एम0एल0ए0 द्वारा पे पढ किये गये रैजोल्यू टान पर बहस जारी होगी। इस रैजोल्यू टान पर उस दिन चौधरी संत कंवर बोल रहे थे, वे कृपया अपना भाषण जारी करें।

**चौधरी संत कवर (हसनगढ़):** स्पीकर साहब, चौधरी कंवल सिंह जी ने जो प्रस्ताव पे किया है कि हरियाणा में आई०ए०एस० काडर की संख्या न बढ़ाई जाये और हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव को कम किया जाए। मैं इस पर पांच सात मिनट अपने विचार रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार आने के बाद जिन आई०ए०एस० अफसरों की 9 साल की सर्विस थी उन सब को जवायंट सैक्रेटरी के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। इससे सरकार के उपर 250 रूपये प्रति मास एक अफसर के हिसाब से खर्च पडा है पीछे पंजाब और हरियाणा के अन्दर डिप्टी कमिशनर भी अंडर सैक्रेटरी के रैंक के होते थे ओर आज भी अंडर सैक्रेटरी के रैंक के है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में दस साल की सर्विस के बाद अंडर सैक्रेटरी का रैंक दिया जाता है और हमारे यहां 9 साल की सर्विस के बाद यह रैंक दे दिया गया है। इससे प्रान्तीय सरकार के उपर फाइनेंशियल बोझ पडा है। सपुलिस के अन्दर हमारे आई०जी० साहब आज भी जवायंट सैक्रेटरी रैंक के है जबकि उसको सैक्रेटरी रैंक का होना चाहिये। वह सारे हरियाणा की पुलिस का एक जिम्मेदार अफसर है। वह तो जवायंट सैक्रेटरी के रैंक का है लेकिन दूसरे आई०ए०एस० अफसर जिनकी 9 साल की सर्विस हो चुकी है उनको जवायंट सैक्रेटरी के रैंक का बना दिया गया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये) इसलिये मैं सरकार के नोटिस में यह मामला लाना चाहता हूँ कि आज आई०ए०एस० अफसरों की भर्ती कम की जाये। पिछले दिनों आपने अखबार में पढा होगा कि 60 प्रतिशत आई०ए०एस० अफसर वे है



जिनके मां बाप पहले आई०ए०एस० अफसर थे। इन 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत आई०ए०एस० वे अफसर हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं इस हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम करने की मांग इसलिये की जा रही है ताकि जो लोग दूसरे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं या जो लोग हरियाणा की सर्विसीज में हैं उन लोगों को भी इस सर्विस में आने का मौका मिल सके। यह परसैंटेज भी तब बनती है जबकि हमने 20 प्रतिशत पोस्टें हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज और दूसरों के लिये रिजर्व रखी है। अगर यह रिजर्वेशन नहीं होती तो आज उन अफसरों की परसैंटेज 60 की बजाये भायद 80 होती, जिनके मां बाप पहले आई०ए०एस० अफसर थे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बात मानता हूँ कि हमारे बहुत सारे आफिसर ईमानदार हैं और बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ। आठ साल पहले की बात है। अम्बाला में एक डी०सी० होते थे। उनके पास दूसरे आई०ए०एस० आफिसर, जो ट्रेनिंग के लिये वहां भेजे गये थे, डिप्टी कमिशनर की कोठी में धान की खेती हो रही थी। उस धान की खेती को देखकर उन अफसरों में से एक अफसर ने कहा कि आप की कोठी में बहुत घास हो रही है इसे कटा दिया जाये। कहने का मतलब यह कि जिन अफसरों को हरियाणा के कल्चर और एग्रीकल्चर आदि के बारे में मालूम नहीं है जो विभाग उनको सौंपा जायेगा, उसकी जिम्मेदारी किस प्रकार सम्भालेंगे? इसलिये चौधरी कंवल सिंह ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है कि आई०ए०एस० कैडर के अफसरों की संख्या कम की जाये, मैं इसका

समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूँ। मैं ओर भी बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ हरियाणा की बहुत सी कार्पोरेट एज में मैनेजिंग डायरेक्टर आई०ए०एस० आफिसर लगा रखे है। मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि कई कार्पोरेट इन घाटे में चल रही है। इसकी क्या वजह है? इन कार्पोरेट एज को घाटे में चलाने की जिम्मेदारी इन अफसरों पर ही है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो आई०ए०एस० अफसर धान की फसल को घास कह सकते है वे प्रदेश का विकास किस प्रकार कर सकते है? आई०ए०एस० अफसर एक एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिये। अगर इस प्रकार के मैनेजिंग डायरेक्टर लगाये जायेंगे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कार्पोरेट एज फायदे में चलेंगी और इनसे स्टेट को फायदा होगा।

**चौधरी पीरचन्द:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े केडर के लिये इन्होंने इतनी अदनी बात कैसे कर दी है? इन अफसरों को सारे हिन्दुस्तान के बारे में बताया जाता है। इनका एक स्टैटस होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये भला कैसे धान को घास कह सकते है? (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुये)

**चौधरी संत कंवर:** चेयरमैन साहब, चौधरी पीरचन्द जी मेरी बात को चैलेज करें, इस आउस में चैलेज करे। मैं ऐसे अफसरों के नाम बता सकता हूँ और साथ ही गवाहियां दे सकता

हूँ। चेयरमेन साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कार्पोरेट इंजिनेरिंग घाटे में चल रही है उनका घाटे में चलने का कारण आई0ए0एस0 अफसर भी है क्योंकि वे पूरी जानकारी नहीं रखते हैं।। अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कार्पोरेट इन है तो एग्रीकल्चर से संबंधित क्लास के रहने वाले को, हरिजन को कार्पोरेट इन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाये। दूसरी सबसे बड़ी बात चेयरमैन साहब, यहां जिस तरीके से मंत्री अपना विभाग संभालते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है अगर कोई अफसर खराब काम करता है तो मंत्री उसकी ए0सी0आर0 खराब कर सकता है। कार्पोरेट इन के मैनेजिंग डायरेक्टर को सारी पावर है उसको कोई चेयरमैन चैलेंज नहीं कर सकता है, चेयरमैन की जिम्मेवारियों है लायबिलिटीज है वह उसके उपर आती है परन्तु कोई भी अफसर उसके पास नहीं आता है कोई फाइल नहीं लाई जाती। चेयरमैन साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि चेयरमैन के पास इतनी पावर होनी चाहिये जैसे मंत्री के पास अफसर की ए0सी0आर0 लिखने की होती है वह उसकी ए0सी0आर0 लिख सकें चेयरमैन साहब, जब तक इस और ध्यान नहीं दिया जायेगा, कांडर और भर्ती पर रोक नहीं लगाई जायेगी, तो इस हैवी एडमिनिस्ट्रेशन इन पर खर्च होता रहेगा। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि इस रैजोल्यूशन इन का पास किया जावे। मुख्यमंत्री जी इस रैजोल्यूशन इन को पास करने के लिये पुख्ता कदम उठाये।

श्री भलेराम (बड़ौदा-अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, जो आई०ए०एस० के केडर की संख्या कम करने का प्रस्ताव पे किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हरियाणा में 152 आई०ए०एस० अफसर है हर महीने प्रति व्यक्ति 4-5 हजार रूपये लेता है। इस तरह लगभग 60 लाख रूपये हर साल इन पर लगाये जाते है सारे हिन्दुस्तान मे से 82 प्रति शत भाहरों से आई०ए०एस० अफसर लिये जाते है और 18 प्रति शत देहातों से लिये जाते है। इसलिये जो देहात वाले है, हरियाणा के आई०ए०एस० अफसर है और दूसरी स्टेटस को डैपूटे शन पर गये हुये है, उनको वापिस हरियाणा में बुलाया जाये ताकि वे अपनी स्टैट की सेवा कर सकें, उनको हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया जाये। अगर हरियाणा के अफसर होंगे तो वे गांवों का विकास करने में मदद करेंगे, इस तरफ ध्यान देगे। यह ठीक है आई०ए०एस० अफसर का एक स्टैंडर्ड होता है। वह जिस माहौल में पढा लिखा होता है उसको सरकार भी मेनटेन करती है। परन्तु सरकार की किसी आर्थिक नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिये अगर देरी होती है तो इनके कारण होती है। यह नहीं होनी चाहिये। जो फाईल दो दिन में पूरी होनी चाहिये वह दो महीने में होती है। वे अफसर उस नीति को इम्प्लीमेंट करके सुधार करने की कोशिश करें। किसी भी सरकार की सफला और असफलता इन आई०ए०एस० अफसरों पर ही होती है। कार्पोरेट शर्ज में ऐसे आई०ए०एस० अफसर होने चाहिये जो देहात से हों। जैसे रूरल डिवैल्पमेंट कार्पोरेट शन है। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि

उसने गांवों के बारे में उनके विकास के बारे में सोचना हैं यहां जैसे सड़कें बनाने का काम है और भी बहुत से काम है। अगर वह देहात से पढ़कर आई0ए0एस0 बना है तो वह वहां कामयाब हो सकता है। चेयरमैन साहब, इन आई0ए0एस0 अफसरों को देहात का हित सोचना चाहिये क्योंकि उनको भी पता है कि जो तनखाहें वे लेते हैं वे सभी इन देहात के लोगों पर टैक्स लगा कर उनको मिल पाती है। गांवों में 80 प्रति शत लोग रहते हैं। इसलिये इन लोगों की तनखाह इनके सिर पर ही आती है। जो सरकार की नीति है कि गांवों पर हम 45 करोड़ रुपये खर्च करें तो इन आई0ए0एस0 लोगों को इसको अच्छी तरह खर्च करना चाहिये। इन भावों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो देहात के आई0ए0एस0 अफसर हैं उनको वापिस हरियाणा में बुला लेना चाहिये। और इनकी संख्या से सरकार को परेशानी नहीं होनी चाहिये इन भावों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूँ।

**श्री हरफूल सिंह (फतेहाबाद):** चेयरमैन साहब, यह जो आई0ए0एस0 अफसरों के बारे में रैजोल्यूशन आया है मैं इसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ। हरियाणा स्टेट के हर डिपार्टमेंट का हैड एक आई0ए0एस0 अफसर है। हर डिपार्टमेंट का सैक्रेटरी आई0ए0एस0 अफसर है। चीफ इंजीनियर की टैक्नीकल पोस्ट होती है लेकिन उसका हैड आफ दि डिपार्टमेंट एक नान-टैक्नीकल आई0ए0एस0 अफसर होता है। चाहे कोई भी महकमा है, चाहे

हपुलिस का महकमा है, चाहे बिजली का महकमा है , चाहे नहर का महकमा है जहां पर चीफ इंजीनियर होता है इन सब महकमों में आई0ए0एस0 अफसरों को हैड आफ दि डिपार्टमेंट लगाया हुआ है। ये आई0ए0एस0 अफसर आहिस्ता आहिस्ता सब महकमों पर छा गये है। यदि कोई टैक्नीकल महकमा है तोवहां पर भी नान-टैक्नीकल आई0ए0एस0 अफसर ही हैड आफ दि डिपार्टमेंट होता हे। जब कोई आई0ए0एस0 अफसर टैक्नीकल पोस्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं तो उसको उस टैक्नीकल महकमें का हैड आफ दि डिपार्टमेंट नहीं लगाना चाहिये। चेयरमैन साहब, इसीलिये तो यह सारे काम खराब होते है वोकि जो आई0ए0एस0 अफसर टैक्नीकल काम के बारे में कुछ नहीं जानता उसको उसका हैड आफ दि डिपार्टमेंट लगा दिया जाता है। इसलियेमें कहना चाहता हूं कि जो टैक्नीकल महकमें है उनमें टैक्नीकल अफसरों को ही लगाना चाहिये। दूसरे आई0ए0एस0 अफसरों को उनका हैड आफ दि डिपार्टमेंट नहीं लगाना चाहिये। दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त में बहुत ज्यादा कापोरे ंज खोल दी गई है और उन सब के हैड आफ दि डिपार्टमेंट एम0डी0 है जोकि आई0ए0एस0 होते है। हरियाणा प्रान्त मे कापोरे ंज ज्यादा से ज्यादा 20-25 होगी और आई0ए0एस0 अफसर 152 है और इन आई0ए0एस0 अफसरों को खुद ही नहीं पता है कि हरियाणा के अन्दर कितनी कापोरे ंज है। इन आई0ए0एस0 अफसरों के लिये क्या होता है कि खोल दी कापोरे ंज लगा दिया एम0डी0। इस तरह से नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं सरीकार से अर्ज करूंगा

कि कम से कम जिस आदमी को जिस महकमे के बारे में पूरी जानकारी हो उसी आदमी को उस महकमे का हैड आफ दि डिपार्टमेंट लगाना चाहिये। चेयरमैन साहब, अब मैं इनकी फ़ैसीलिटीज के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिले में एक डी०सी० आई०ए० एस० अफसर होता है उसका घरेलू काम करने वाले कम से कम 20 सरकारी कर्मचारी मिलेंगे। वह क्या करते है कोई माली का काम करता है, एक भैंस चराने का काम करता है, एक उसकी कार को साफ करता है और एक उसके जूतों की पालि । करता है। इस तरह से उसके चारों और बीसों आदमी चिपटे रहते है। चेयरमैन साहब, इसके बारे में सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन पर रोकथाम लगानी चाहिये। चेयरमेन साहब पिछले दिनों फ़ूड एंड सप्लाइज महकमे के 171 आदमी बेकार हो गये। इनके बारे में मैंने जब मुख्यमंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब सरप्लस में चले गये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या कभी ये आई०ए०एस० अफसर भी सरप्लस हुये है? ये नहीं होते, क्योंकि इनके लिये कार्पोरे ांज खोल दी जाती है और एम०डी० लगा दिये जाते है। मैडीकल के बारे में चाहे आई०ए०एस० अफसर कुछ न जानता हो लेकिन डाक्टरों की ए०सी०अर० भी आई०ए०एस० अफसर लिखेगा। एक आई०ए०एस० अफसर को नहर के ऐस्टीमेट के बारे मे कुछ नही पता होता लेकिन उसको नहर का हैड आफ दि डिपार्टमेंट लगा दिया जाता है जैसे वी०पी० जौहर है वह बिजली बोर्ड के चेयरमैन है। इसलिये मैं सरकारसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उसी आदमी को महकमे का हैड आफ दि

डिपार्टमेंट लगाना चाहिये जो उस महकमें के बारे में परी जानकारी रखता हो। इन भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री देवेन्द्र भार्मा(थानेसर):** मैं कुछ चटपटी बातें कहने के लिये खडा हुआ हूं। भायद मेरी बात कुछ साथियों को कुछ न लगे। हम इन आई0ए0एस0 अफसरों के पीछे इतने पड़े हुये है लेकिन मैं यह समझता हूं कि हम थोड़ी गलती करते जा रहे है। जाहं तक इन आई0ए0एस0 अफसरों का सवाल है मैं तो इनको बेसीकली इनटैलीजेंट क्लास में गिनता हूं क्योकि कोई भी इस क्लास में सिफारि 1 से नहीं आता जबकि एक आदमी एम0एल0ए0 बिना सिफारि 1 के नहीं बनता। एम0एल0ए0 बनने के लिये लोगों के आगे हाथ जोडने पडते है उनसे कहते है कि चल भाई मेरी स्पोर्ट कर, चल भाई मुझे टिकट दिलवा लेकिन आई0ए0एस0 अफसर कोइ भी सिफारि 1 से नहीं बनता। यह बैसीकली इनटैलीज क्लास है। इसको अगर हम इग्नोर करके चलें तो यह हमारे लिये ठीक नही है। रही बात टैक्नाक्रेटस की, इनका जहां तक ताल्लुक है, मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो टैक्नीकल जगह है वहां पर टैक्नोकेटस को ही लगाना चाहिये। आपकी मारफत चौधरी साहब को यह बता दूं कि टैक्नोकेटस भी आई0ए0एस0 के कम्पीटी 1न में हिस्सा ले सकता है , एक एम0बी0बी0एस0 बन सकता है और इसी तरह एक इंजीनियर भी आई0ए0एस0 अफसर बन सकता है लेकिन उनमें यह



हिम्मत होनी चाहिये कि वह कम्पीटीशन में हिस्सा लें और आई०ए०एस० बन करके दिखाये। चेयरमेन साहब, जहां तक आई०ए०एस० अफसर का ताल्लूक है ये 50 परसेंट दूसरी स्टेट के होते हैं और 50 परसेंट उसी स्टेट के होते हैं। जैसे चार आई०ए०एस० अफसर लेने हैं तो 2 उसी स्टेट के होंगे और दो दूसरी स्टेट के होंगे आई०ए०एस० अफसर बहुत बड़ी-2 पोस्टों पर होते हैं। जैसे हमारे डी०सी० आई०ए०एस० अफसर होते हैं और एस०डी०एम० भी अमूमन आई०ए०एस० होते हैं। ( गोर) तो चेयरमैन साहब, इन पर पक्षपात का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है। अगर किसी भी लोकल आई०ए०एस० अफसर को डी०सी० लगा दिया जायेगा तो वह चीफ मिनिस्टर के कहने से एक इंच भी इधर उधर नहीं जा सकता चीफ मिनिस्टर चाहे चौधरी साहब है, चाहे कोई भी रहे वह चीफ मिनिस्टर के कहने पर चलेगा। ( गोर)

**श्री हरफूल सिंह:** चेयरमेन साहब, भार्मा जी ने बताया कि एक डाक्टर भी आई०ए०एस० के कम्पीटीशन में आ सकता है। यह मैं मानता हूँ कि आ सकता है लेकिन मैंने तो कहा था कि उसको उसी महकमें न लगायें जिसके बारे में वह पूरी जानकारी रखता है।

**श्री देवेन्द्र भार्मा:** चेयरमेन साहब, मेरी गुजारि है। इसमें यह है कि 50 परसेंट जो बाहर से आयेगे उनके उपर हम पक्षपात का आरोप नहीं लगा पायेंगे। एक चीज मैं और मानता हूँ कि

इनटैलीजेंसी और इन्टेग्रेटी के हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आई०ए०एस० अफसरन बहुत इनटैलीजेंट और ईमानदार होते हैं।

**श्री हरफूल सिंह:** चेयरमैन साहब, मैंने इनके उपर कोई झूठा करण्डान का इल्जाम नहीं लगाया है।

**श्री देवेन्द्र भार्मा:** चेयरमैन साहब, बात कहने के लिये कुछ प्वायंट तो देने ही पड़ेगें। स्टैट में कोई भी काम हो, सरकारचाहे कांग्रेस की रहे, चाहे जनता की रहे ओर चाहे किसी पार्टी की रहे, अल्टीमेटलीसारी जिम्मेदारी आफिसर्ज के उपर जाती है। चेयरमैने साहब, एच०सी०एस० अफसर या कोई क्लर्क परमोट करके डी०सी० लगा देंगे तोउनकी जिम्मेदारी क्या होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बात करने से हमारे अफसर दिन प्रतिदिन डिमारेलाईज होते जा रहे हैं। इसको मैं एकमिसाल देता हूँ। पिछली सरकार का लोगों के दिमाग में यह इम्प्रे न है कि पिछली सरकार ने जो काम किये हैं अब ऐसे नहीं हैं मैं। तो कहता हूँ कि आज उनसे भी ज्यादा काम करने की कोशिश की जाती है पहले कौन सा चीफमिनिस्टर 24 घंटे काम करने वाला था? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सारे देा में पहले चीफ मिनीस्टर है जोकि बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। लेकिन उतना काम ये इसलिये नहीं करपाते क्योंकि ये अपने आफिसर्ज को कान्फिडेंस से नहीं चला पाये हैं। चीफ सैक्रेटरी सबसेस बडा आई०ए०एस० अफसर होता है। और सबसेस बछोटा अन्डर सैक्रेटरी

होता है। जिसको आजकल एस0डी0एम0 बनाया जाता है। चेयरमैन साहब, अगर कहीं झगडा हो जाता है उसकी न तो एस0पी0 जिम्मेवारी लेता है ओर न ही सैकेटरी जिम्मेवारी लेता है। अगर वह कहीं लाठी चार्ज का हुक्म दे दे औरउसके विरुद्ध इन्क्वायरी हो जाए तो उसको सस्पेंड कर दिया जायेगा। चेयरमैन साहब, मैं एक बात ओर कहना चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम जी हिन्दुस्तान के डिप्टी प्राईम मिनिस्टर है। जब रोहतक में आये तो वहां पर जो कुछहुआ उसकी न तो डी0सी0 ने जिम्मेवारी ली और न ही एस0पी0 ने जिम्मेवारी ली। उसकी इनकवायरी भी हुई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। (विघन) चेयरमैन साहब, इकोनोमी की बात भी यहां कही गई लेकिन इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में बडी भारी फजूलखर्च की जाती है। कहीं पर सी0एम0 दौर पर जाये, प्राईम मिनिस्टर दौर पर जाये या राष्ट्रपति दौरे पर आ जाये तो बडे बडे इन्तजाम किये जाते है। सडकों की डैकोरे उन पर लाखों रूपया खर्च किया जाता है, रंग बिरंगे झंडियां, रंग बिरंगे बुर्ज बनाये जाते है और सारा पैसा बेकार में खर्च किया जाता है.....(विघन)

**श्री सभापति:** आपकी बात आ गई है, अब आप बैठ जाइये। अब चौधरी रिजक राम बोलेंगे।

**चौधरी रिजक राम (राई):** चेंयरमैन साहब, इस प्रस्ताव पर पहले भी काफी चर्चा हुई और आज भी बहस जारी है। मेरे साथी चौधरी हरफूल सिंह तथा श्री संत कंवर ने कई पवांयट रेज

किये है। चेयरमैन साहब, किसी कारपोरेट्स में या किसी अंडरटेकिंग में, जहां तक आई0ए0एस0 आफिसर लगाने का सवाल है, वह अन-ट्रेंड नहीं होना चाहिये, इससे कई खराबियां पैदा हो जाती है। असल में हरियाणा प्रदेश में जो सबसे बड़ी कमी है वह है ट्रेंड होनी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे मैनेजिरियल स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। किसी कारपोरेट्स में लगने के बाद काम सीखना शुरू करते हैं। जैसे भूगर मिल में अन-ट्रेंड आदमी को लगा देते हैं और जब तक वह काम सीखता है तब तक सारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव खराब हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी कारपोरेट्स हैं या पब्लिक अंडरटेकिंग है उनमें ट्रेनिंग के बाद ही आई0ए0एस0 आफिसर को लगाया जाये। यही कारण है कि आज मैक्सिमम कारपोरेट्स हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग घाटों में चल रही है और इनकी हालत सुधारने के लिये आत तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाये गये और न ही कभी सोचा गया कि ये घाटे में क्यों चल रही हैं। आई0ए0एस0 आफिसर कम हों या ज्यादा, इस पर हमारे वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री खुद ही विचार कर रहे होंगे, मैं इसके बारे में जादा नहीं कहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे खुद ही सारे हालात को देखते हुये जो फैसला करेंगे वह ठीक ही होगा लेकिन एक बात आपकी इजाजत से जरूर कहूंगा कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, हमने उसको चेंज किया, एक नया विधान बना, पार्लियामेंट ने उसके मंजूर किया और यह

सारी कार्यवाही होने के बाद वह विधान यानि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सारे दे में लागू हो गया। आज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मीनरी है.....

**श्री देवेन्द्र भार्मा:** स्पीकर साहब, मुझे अपने प्वायंट आफ आर्डर कह कर बैठाया था क्योंकि मैंने समझा था कि चौधरी रिजक राम प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुये है। मैंने अभी बहुत कुछ कहना है। वैसे तो जो कुछ मैंने कहना था वही बात ये भी कह रहे है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप बैठ जाइये।

**चौधरी रिजक राम:** चेयरमैन साहब, विधान एक्सैप्ट होने के बाद हमने देश में भासन प्रणाली का ढांचा तैयार किया। इस ढांचे में एक विंग परमानेंट सर्विसिज का है, एक जुडी ग्यरी का है ओर एक लैजिस्लेचर्ज का हैं। परमानेंट सर्विसिज से मेरा मतलब एग्जैक्टिव से है। डेमोक्रेसी में अगर पोलिटिकल विंग न हो तो भी जनता में अंसतोश रहेगा, अगर परमानेंट सर्विसिज का विंग मजबूत न हो तो दे ग की डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती और अगर जुडी ग्यरी कमजोर हो तो देश में अत्याचार होने भुरू हो जाते है। तो परमानेंट सर्विसिज जहां तक ताल्लुक है इसके तजर्बे को हमें एक्सपैट करना चाहिये। आप देखें, हम असैम्बली में आये, मुख्य मंत्री बनाया ओर मुख्य मंत्री ने कैबिनेट बनाई। सारे नुमायंदे राज करने लग पड़े, चाहे उनका राज करने का तजर्बा है या नहीं,

लेकिन उनको पब्लिक का मैडैट है, पब्लिक ओपीनियन को साथ लेकर असैम्बली में आये है। इनहोने पब्लिक के सामने कोई प्रोग्राम रखा था जिसकी बिना पर वोट लेकर असैम्बली में आये, लेकिन इनको राज करने का तजूर्बा नहीं होता। जो प्रोग्राम लेकर आते है उसको लागू करने के लिये एच0सी0एस0 आफिसर बैठे है। कैबिनेट जो नीति निर्धारित करती, वह जनता के मैडैट के बैसिज पर करती है, जनता उनको सिखाती हे कि ऐसा करो, लेकिन कैबिनेट को नीति निर्धारित करने का तजूर्बा नहीं होता। नीति निर्धारण में परमानेंट सर्विसिज का बहुत ज्यादा गहरा सम्बन्ध है। उनको जो भाक्ति मिली है उसके कारण ही उनका तजूर्बा है। परमानेंट सर्विसिज एक मुस्तकिल पावर है। कांग्रेस भासनकाल में, जब बंसी लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस जमाने में भी परमानेंट सर्विसिज बंसी लाल की, कैबिनेट की लायल रही। लायलटी इनका ध्येय है ओर जा `नीति कैबिनेट निर्धारित करे, वे उसको सिंसीयरली इम्पलीमेंट करेगें। परमानेंट सर्विसिज इम्पलीमेंटे इन की मीनरी है। अगर हम यह कहें कि पालिटिियन्ज ही प्रान्त का भासन चला सकते है तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत सी बातों का पता नहीं। वे सर्विसिज जो मुस्तकिल तौर पर रहती है उनको हर विभाग के बारे में पता होता है ओर पालिटिियन्ज के लिये, पोलिटिकल लीडर्ज के लिये एक गाइड लाईन हेते है। कहने का मतलब यह है कि पोलिटिकल विंग और परमानेंट सर्विसिज का विंग, दोनों की इस देा में जरूरत है। इन में से किसी एक को इग्नोर करके अगर

हम यह सोचें कि देश का काम काज चल जायेगा, बिल्कुल गलत बात है। परमानेंट सर्विसिज को डीमौरलाईज करके अगर देश का काराबार चलाना चाहे तो चल नहीं सकता। आप देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है? इसलिये बनाया है कि परमानेंट सर्विसिज एक गाईड के तौर पर काम करती है और दूसरे इन्होंने चैक्स एंड बेलेसिंज प्रोवाईड किया है ताकि कोई नया आदमी, अगर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन जाता है, ये उसको गाईड कर सके, क्योंकि वह ना-तजर्बेकार होता है और उसके पीछे लोगों का पोलिटिकल प्रैर होता है, जनमत से आये है, इसलिये जनताउनसे बहुत कुछ उम्मीद करती है। इस पोलिटिकल प्रैर के नीचे ये गलत काम न करे, इस अवसर पर आफिसर का काम बन जाता है कि वह उनको ठीक ठीक सला दे। आज जरूरत इस बात कह है, मैं बजट प्वांयट आफ व्यू से नहीं कह रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्वांयट आफ व्यू से कह रहा हूं। आज जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी अपने वि वास के मुताबिक आफिसरों को रखे। अब इनके ट्रांसफर की बात आती है। पटवारी के लैवल से लेकर उपर तक ट्रांसफर करवाना जो चाहता है पोलिटिकल प्रैर की वजह से हम कोर्ता करते है कि मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करने के आर्डर करें, इस पालिसी से परमानेंट सर्विसिज बहुत परे गान है। कैबिनेट को परे गानी है, मुख्य मंत्री को परे गानी है आफिसरज को परे गानी है। पोलिटिकल इन्टरफायरेंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। कोई ट्रांसफर करवाता है, दूसरा उसको

रुकवाता है, ऐसा नहीं होना चाहिये। जो नीति हमने घोशणा-पत्र में दी है, उसके मुताबिक पालिसी बने और आफिसरज के जिम्मे लगायें कि वे उस नीति को इम्पलीमेंट करें। पालिसी को इम्पलीमेंट करने में अगर कोई आफिसर कोताही करता है तो उसके खिलाफ ऐक्टान ले। इस बिना पर दखल देकर ऐक्टान लेना तो इनकी जिम्मेवारी है, लेकिन अननसैसरी हर मामले में दखल हो, पालिसी को इम्पलीमेंट करने में रूकावट पैदा करे तो मैं समझता हूँ कि हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिये। चेयरमैन साहब, एक बात और कहना चाहता हूँ। जो परमानेंट सर्विसिज है, इनका रोल कार के ड्राइवर की तरह होता है। कैबिनेट कार का मालिक है और आफिसर उसको चला रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि आफिसर लोग हर बात को कहें कि ठीक है जो ठीक होगी उसको ठीक कहें, जो गलत हो उसको गलत कहें जो भी कहना चाहते हैं वे पोलाइटली कहें। आफिसर गलत बात को गलत कह सकता है क्योंकि वह कार के ड्राइवर की तरह होता है। अगर ड्राइवर कार को समय पर न रोके तो कार गड्डे में पड़ेगी उसका फर्ज बनता है कि वह साफ-2 कह दे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, ऐमरजेंसी लागू हुई उसके बाद कोई आफिसर अपने किसी मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री को यह नहीं कह सका कि फलां बात गलत हैं वे बड़े डिमोरेलाइज हुयें। इसका नतीजा चेयरमैन साहब यह निकला कि जो कांग्रेस पार्टी तीस साल से राज कर रही थी उसको लोगों ने पछाडा और जनता पार्टी का राज हुआ। वह मिसाल हमारे सामने है। हमें



चाहिये कि हम ओफिसर्ज को डिमोरेलाइज न होने दे। मैं संत कंवर जी को यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मान लो कार्पोरे इन में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक एम0एल0ए0 चेयरमेन है। अगर एम0एल0ए0 न तजुर्बेकार है तो वह उस मैनेजिंग डायरेक्टर की मदद की बिना कामयाब नहीं होगा। उस एम0एल0ए0 को काम सीखने में अभी टाईम लगेगा। मैं सर्विसिज के आदमियों से भी यह प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाब्द हमारे मुंह से निकले वह ऐसा न हो कि कोई अफसर यह समझे कि उन पर आक्षेप हो रहा है। अपने घरों में वे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं लेकिन अगर वे कोई गलत काम करते हैं या किसी छोटे चपडासी को गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो बे तक आप उनके खिलाफ ऐक्ट इन लें। चौधरी हरस्वरूप बूरा ने बिल्कुल ठीक बात कही। किसी दे में भी खूनी क्रांति तब आती है जब सर्विसिज का प्रैसटिज खत्म होता है। अगर उनका प्रैसटिज नहीं रहता है तो पोलिटिकल लीडरशिप जनता को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हम अपने अफसरों पर यकीन करें, उनको ड्यू रिसपैक्ट दें और अपने प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में उनका कोआपरेशन हासिल करें ताकि पांच साल के लिये जो हम यहां चुन कर आये हैं इस कार्यकाल को हम सफलता से पूरा करें।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम):** सभापति महोदय, मेरे भाई कंवल सिंह जी हाउस के सामने जो रैजोल्यूशन लाये हैं उस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। सवाल हमारे सामने यह है कि स्टेट का खर्चा किस तरह बचाया जाये। चेयरमैन साहब, जहां तक ऑफिसर्स के खर्च का सवाल है या ऐफिंसाएँसी का सवाल है इसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी पोलिटिकल इंटरफीयरेंस होती है जिसकी वजह से हमारे ऑफिसर्स के खर्च का सवाल है या ऐफिंसाएँसी का सवाल है। इसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी पोलिटिकल इंटरफीयरेंस होती है जिसकी वजह से हमारे ऑफिसर्स डिमोरेलाइज हो चुके हैं। अगर हमने ऑफिसर्स से सही मायनों में काम लेना है तो हमें इसकी तरफ पूरा ध्यान देना होगा। सरकार को अपने ऑफिसर्स के अन्दर कांफिडेंस कियेट करना होगा। केवल बातों से या कहने से कि आई०ए०एस० के डर को बन्द कर दिया जाये काम नहीं चलता। बेसिक चीज तो यह है कि पोलिटिकल इंटरफीयरेंस बिल्कुल बन्द होनी चाहिये जिससे ऑफिसर्स डिमोरेलाइज न हो। दूसरे सर्विसिज के अन्दर गवर्नमेंट को कांफिडेंस कियेट करना चाहिये। इसके अलावा मेरी अर्ज यह है कि महकमों के और कार्पोरेट्स आदि के जो लोग सर्वेसर्वा हैं उनको अपने ऊपर कुछ पाबन्दी लगानी होगी, उन्हें स्वयं एक उदाहरण पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐफिंसाएँसी नहीं आ सकती। आज चूंकि सवाल सारी स्टेट में खर्च कम करने का है इसलिये मैं वालेंटैरिली ऐलान करता हूँ कि

दो अप्रैल सन् 1979 से कार्पोरेट्स की चेयरमैनशिप से मेरा इस्तीफा समझा जाये। (प्र. संसा)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

**श्री सभापति:** अब आप बैठिये। मंत्री जी को बोलने दे।  
तीन रैजोल्यूट्स और है उन पर बोल लेना।

**वित्त मंत्री (श्री मूलचन्द जैन):** चेयरमैन साहब, यह जो प्रस्ताव मेरे नोजवान साथी श्री कंवल सिंह जी ने रखा है इससे तीन मतलब निकलते हैं। प्रस्ताव यह है कि राज्य में टॉप हैवी प्रोविजन में मजिद इजाफा रोकने के पैसे नजर हाउस सिफारिश करता है कि राज्य में कम से कम पांच वर्षों तक आई०ए०एस० कैडर की स्ट्रैन्थ में किसी भी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं और इसके लिये सरकार प्रभावशाली कदम उठाये।

चेयरमैन साहब, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इस प्रस्ताव में मुझे तीन बातें मालूम होती हैं। नं० 1, हमारे राज्य में टॉप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव है, यह प्रिज्युम करके यह प्रस्ताव दिया गया है। नं० 2, वे मानते हैं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव का कारण आई०ए०एस० अफसरान है। नं० तीन बात यह है कि उन्होंने सुझाव दिया है कि पांच वर्षों तक अगर आई०ए०एस० ऑफिसर्स की जो गिनती है उसको न बढ़ाया जाये तो टॉप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव भी ठीक हो जायेगा और आई०ए०एस० ऑफिसर्स है उनकी गिनती भी कम होती चली जायेगी। जहां तक टॉप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव का

ताल्लूक है, अभी बजट पर जनरल डिसकशन में भी ओर उसके बाद डिमांडज पर बोलते हुये भी काफी सदस्यों ने इसके बारे में जोर दिया ओर सरकार यह मानती है कि टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन को कम करने की गुंजायश है। मैंने बजट के उत्तर में भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि सरकार उस टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन को कम करने के लिये जितने भी कदम उठाये जा सकते हैं। उठायेगी लेकिन उस टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन की जिम्मेदारी आई०ए०एस० अफसरान पर है इससे मेरा मतभेद है। जिम्मेवारी अगर है तो हमसब पर है। मेरा ख्याल है कि पुराने आई०सी०एस० ऑफिसर्स के जो संस्कार थे, अंग्रेजों के बारे में जो हमारे विचार थे, वही भायद कुछ लोग आई०ए०एस० ऑफिसर्स के बारे में अपने मन में लाने लगे हैं हालांकि इन दोनों को जोड़ना गलत है। ये आई०ए०एस० वाले हमारे भारतीय हैं हमारे बच्चे हैं, इनमें से कुछ हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये कोई बाहर से नहीं आये हैं आई०सी०एस० वाले तो प्रयत्नः बाहर से आये हुये थे। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इनके बारे में आई०सी०एस० वाले संस्कार मन में लाना ठीक बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी स्टेट में आई०ए०एस० अफसर कम हैं लेकिन मैं यह जोर से कहना चाहता हूँ कि उनमें भी वहीं गुण हैं जो दूसरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों में हैं और वही दोष है जो भारत के अन्य बुद्धिजीवियों में है चाहे कोई बिजनैस में हो, चाहे प्राइवेट डाक्टर हो या इंजीनियर हो उनमें भी वहीं गुण-दोष है जो आई०ए०एस० अफसरों में है। यह कहना कि आई०ए०एस०

अफसरों में हैं यह कहना कि आई०ए०एस० अफसरों में ज्यादा दोष है, बिल्कुल गलत बात है। भारत के जो एम०ए० ओर बी०ए० में टाप स्टुडेंट्स होते हैं वहीं आई०ए०एस० में आते हैं। सारे हिन्दुस्तान में मुकाबला होता है जो टाप पर आते हैं उनको पब्लिक सर्विस कमी इन रिकमेंड करता है। जितने लेने होते हैं उनमें से लिये जाते हैं। चेयरमैन साहब यह यकीन से कहा जा सकता है कि भारत के बुद्धिजीवी नौजवान ही मुकाबले में आते हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इन टाप के स्टुडेंट्स में से कुछ मैडिकल साइड में और कुछ इंजीनियरिंग साइड में चले जाते हैं। जो उस साइड में जाते हैं, वे भी बुद्धिजीवी होते हैं। जो आई०ए०एस० में आते हैं उनमें से मुखातलिफ स्टेट में अच्छे टाप के स्टुडेंट्स होते हैं, वे कम्पीटिशन से आते हैं। उनके प्रति किसी के मन में अगर छुपी हुई दुर्भावना है तो वह गलत बात है। वह हमारे देश के लिये अच्छी नहीं है।

चेयरमैन साहब, एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि पालिटिक्स में, डेमोक्रेसी में पांच वर्ष के पचास चुनाव होते हैं। कोई भी पार्टी इलैक्ट्रॉन में जीत कर आ सकती है। कभी कोई पार्टी आ जाती है और कभी कोई आ जाती है। डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चलाने के लिये स्थायित्व होना जरूरी है और उसमें काम करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेशन में स्थायीपन कायम रख सकते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि उनको किसी तरह से भी डैमेज नहीं

करना चाहिये। अगर उनमें कोई कमी है तो वैसी ही है जैसी और बुद्धिजीवियों में है। इसलिये इस बात को जोड़ना कि टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिये आई०ए०एस० अफसर जिम्मेदार है, यह गलत बात है। जो यह बात कही गई है कि पांच वर्ष के लिये पाबन्दी लगा दी जाये, यह भी गलत बात है, यह बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आई०ए०एस० अफसरों को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों से लिया जाता है। अगर राज्य सरकार चाहती है तो गिनती कम भी हो सकती है। अगर हम पांच वर्ष के लिये बिल्कुल बंद कर दें और आई०ए०एस० अफसरों को यहां नहीं ले तो 10-15 साल के बाद एक ऐसी हालत पैदा हो जायेगी कि जिन अफसरों ने वहां तजर्बा हासिल किया है वे तो उपर चले जायेंगे और नीचे के लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन को आई०ए०एस० अफसर सम्भालते हैं, वह ठीक तरह से नहीं संभल पायेगा। इस तरह से खला पैदा हो जायेगा। अगर 5 पांच साल तक 20-25 अफसर नहीं आयेगें तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इन पर बहुत बुरा असर पड सकता है इसलिये इनका होना बहुत जरूरी है।

एक बात इस सम्बन्ध में और भी कहना चाहता हूं कि मेरे साथी मंत्रियों के लिये और दूसरे सदस्यों के लिये सरकारी कर्मचारियों को दोश देना उचित नहीं। अफसरों को खडे हो कर हम कोस सकते हैं लेकिन मेरा तजर्बा यह है कि सरकारी कर्मचारी एक मजबूत घोड़े की तरह से है। अगर सवार मजबूत होगा तो

उसके काम लिया जा सकता है। अगर सवार ही मजबूत न हो तो घोड़े को दोष देना उचित नहीं है।

**श्रीमती भांति देवी:** आन ए पवांयट आफ आर्डर सर। यह रैजोल्यूय इन टाप हैवी एडमिनिस्ट्रै इन के बारे में है कि आई०ए०एस० अफसरों को कम किया जाये। क्या वे मेंबर्ज जो कार्पोरे इंज के चेयरमैन बने हुये है बूरा साहब की तरह से मिसाल पे आ करेगें। दूसरों को कहने से पहले स्वयं आद र्पे आ करें उसके बाद आई०ए०एस० अफसरों को कहें।

**चौधरी संत कंवर:** यह तो बडा इनटेलीजेन्ट तबका है। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। भान्ति जी भी पहले चेयरमैन थी, यह तो पहले निकाली गई है।

**श्रीमती भांति देवी:** मैंने तो पब्लिकली इस्तीफा तबका है। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। भान्ति जी भी पहले चेयरमैन थी, यह तो पहले निकाली गई है।

**श्रीमती भांति देवी:** मैंने तो पब्लिकली इस्तीफा दिया था।

**श्री सभापति:** कृपा करके आप बैठें।

**श्री मूलचनद जैन:** मैं यह कह रहा थसा कि सरकारी कर्मचारी चाहे आई०ए०एस० है, चाहे पुलिस अफसर है चाहे डाक्टर या इंजीनियर है वे सब क्रीम होते है। इसलिये अगर टोप हैवी

ऐडमिनिस्ट्रे इन है ते उसको कम करना है और करनी चाहिये लेकिन उस कम करने का तरीका जो बताया है उसकी जिम्मेवारी इस रैजोल्यु इन से टपकती है, वह मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से यही निवेदन करूंगा कि वे प्रस्ताव को वापिस ले लें। मैं अ योरेन्स देता हूँ कि टोप हैवी ऐडमिनिस्ट्रे इन की तरफ हमारा पूरा ध्यान है। अब तो बजट भी पास हो गया है और ऐप्रोप्रिये इन बिल भी पास हो गया है। आगे हमारा सारा ध्यान इन बातों की तरफ होगा। इस काम के लिये सारे आई0ए0एस अफसर हमें पूरा सहयोग देंगे और हम भी टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रे इन को कम करना चाहते हैं, इन भावों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

**श्री कवल सिंह (धिराये):** चेयरमैन साहब, अभी जैन साहब ने, मेरे रैजोल्यु इन का जवाब दिया है और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। जैन साहब का चूँकि आदे 1 हुआ है इसलिये मैं रैजोल्यु इन को तो वापिस लूंगा लेकिन मैं दो चार बातें जरूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने टॉप-हैवीनैस का जिक्र किया है। मैं यह मानता हूँ कि वे हमारे प्रान्त की टोप ऐडमिनिस्ट्रे इन को घटाने के लिये और उसके जो अंग है, उनको घटाने के लिये प्रबन्ध कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। आई0ए0एस0 के सारा सैकटेरियेट काबू में है, वे उस पर राज्य कर सकते हैं। मेरा खास प्रस्ताव सबसे पहले यह था कि आई0ए0एस0 की स्ट्रैंग्थ इतनी ज्यादा है, इसको कम करने का



फैसला क्यों नहीं करते हैं। इस बात पर जैन साहब ने रोनी नहीं डाली। हमारा जो संविधान बना है उसमें लिखा है कि यह एक इन्डिपेंडेंट एजेंसी हो और आम सियासतदानों के प्रभाव से दूर रह सके। तभी यह हमारे देश की ऐडमिनिस्ट्रेशन को चला सकेगी लेकिन देखना यह है कि हम इन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को कितनी पावर्ज दे रहे हैं। कई बार हो सकता है पोलिटी गिन्ज में भी वीकनैस आ सकती है जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। जिस समय हमारा आजाद भारत का संविधान बना, उस वक्त हालात दूसरे थे। आज से कई हजार साल पहले वैदिक समाज की स्थापना हुई थी। उसमें इसी प्रकार से कई वर्णों में काम को बांटा गया था। हमने यह देखा कि आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरने के साथ-साथ एक वर्ण ने समाज में अपना ठप्पा कायम कर लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दु धर्म पतन की तरफ चला गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि समाज के एक अंग को इतनी ज्यादा ताकत न मिल जाये कि समय के गुजरने के साथ-2 वह इतना मजबूत हो जाये कि वह उसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार ही समझ ले। जिस तरह से पहले-पहल हमारे समाज के अन्दर ब्राह्मणों को लोगों को पढाने का काम सौपा गया था लेकिन धीरे-2 समय गुजरने के साथ-2 उन लोगों ने इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार ही समझ लिया कि वह ही पढेंगे और वे ही पढायेगे। उसी तरह से हमारा आज का समाज जिसको बने हुये अभी तो 30 साल ही हुये हैं, कहीं 300 साल के बाद इसे भी उसी तरह की समस्या का सामना

न करना पडे। मेरी आई०ए०एस० के खिलाफ कोई जाति दु मनी नहीं है। मैं यह समझता हूं कि वे बाई एंड लार्ज इन्टलीजैन्ट है। लेकिन इनके साथ ही साथ दूसरे इंजीनियर्ज, डाक्टरज यानि टैक्नोकैटस ओर एकेमैडी गियन्ज बगैरा उनसे कहीं ज्यादा काबिल है। आज एक आई०जी० साहब के मुकाबले में सिर्फ 9 साल की सर्विस वाला आई०ए०एस० ज्वायंट सैक्रेटरी उनके बराबर बन जाता हैं ( ओर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब, एमरजैन्सी के दोरान हमारे आई०ए०एस० अफसरान का जब कि पूरा बोलबाला था, ग्रीवीयेंसिज कमेटी के अन्दर हमारे एस.ई० साहेबान जिनका रैंक हमे 11 डी०सी० से उपर रहा है, अग्रेज, जिससे हमने यह ऐडमिनिस्ट्रटिव सिस्टम विरासत में लिया है, उसके जमाने में जिनका रैंक उपर रहा है, उसके बराबर कर दिया गया।.....

**श्री लहरी सिंह मेहरा:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी मेरे साथी माननीय सदस्य ने यह कहा कि 9 साल की सर्विस के बाद एक आई०ए०एस० बहुत ऊंचे पद पर चला जाता है। मैं यह कहता हूं कि एक सदस्य चाहे एक दिन के लिये एम०एल०ए० बन जाये, लेकिन वह आई०ए०एस० से उपर बैठ जाता है।.....

..

**श्री कवल सिंह:** मैं अपने भाई लहरी सिंह को यह बताना चाहता हूं कि मैं लोगों का मैनडेट लेकर आया हूं जैसे वे आये है। मैं दोबारा भी मैनडेट लेकर आउंगा। हम फौज को कितनी अहमीयत देते है। जिस वक्त हमारे बार्डर पर कोठ समस्या

होती है तो हम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं। जब 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई तो उस वक्त नेहरू जी भी नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर जी के एक गाने पर रो पड़े थे। पहले हमारा डी०सी० जो था वह प्रोटोकॉल के अन्दर लैफ्टिनेंट कर्नल के बराबर था, लेकिन अब उसको ब्रिगेडियर के बराबर कर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आहिस्ता-2 ये आई०ए०एस० के लोग अपना मान-सम्मान बढ़ाते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको पूरी तनख्वाह दी जाये, लेकिन इनका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, इसको रोका जाये। मेरे प्रस्ताव के पीछे जो मुद्दा है, वह यही है। मैं यह मानता हूँ कि यह काबिल सर्विसिज है लेकिन हम इन काबिल सर्विसिज को नेता मान कर न चलें। आज से दो-तीन दिन पहले अखबारों में एक खबर भाया हुई थी, और भायद आपे भी पढ़ी होगी। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इन्स्टीच्यूट है (व्यवधान व भाोर) मैं यह रैजोल्यूशन वापिस लेता हूँ और आशा करता हूँ कि जैन साहब और मुख्य मंत्री महोदय इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि आई०ए०एस० के लोगों को हम जितने मान-सम्मान के साथ रखते हैं, उतने ही मान-सम्मान के साथ दूसरे ब्रांचिज के लोगों को, यानि टैक्नोकैटस को और एकेमैडी प्रियन्ज को भी रखेंगे। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है?

**आवाजें:** जी हां।

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।

### सभापति द्वारा घोशणा

श्री सभापति: साहेबान, मुझे अब एक अनाउसमेंट करनी है। जिन मंत्रियों तथा विधायकों ने फरीदाबाद अरबन एस्टेट, सैक्टर-21 ए में प्लाटों के लिये एप्लाई किया है, वे कृपया आज 12 बजे अक्ष महोदय के चैम्बर में आ जायें ताकि उनके सामने लाटरी का ड्रा हो सके।

### गैर-सरकारी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

2. मुख्यमंत्री का एम0एल0ए0 फ्लैटस में रिफिट न करने सम्बन्धी

श्री भागी राम (ऐलनाबाद-अनुसूचित जाति): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

कि इस सदन की यह राय है कि मुख्यमंत्री एम0एल0ए0 फ्लैटस में बदलने की बजाये मकान नं0 1, सैक्टर-3 ए, चण्डीगढ़ में ही ठहरे रहें।

श्री सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि इस सदन की यह राय है कि मुख्यमंत्री एम0एल0ए0 फ्लैटस में बदलने की बजाये मकान नं0 1, सैक्टर-3 ए, चण्डीगढ़ में ही ठहरे रहें।

**चौधरी राम किान (सफीदों):** सभापति महोदय, मेरे साथी ने जो यह रैजोल्यूशन मुव किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ मैं इस रैजोल्यूशन का स्वागत करता हूँ और तमाम हाउस की तरफ से अपने मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है जो ये एम0एल0ए0 फ्लैटस में आये है लेकिन यह हमारे लिये कोई अच्छा कदम नहीं था, सिक्योरिटी प्वायंट आफ व्यू से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से भी। हमारे मुख्य मंत्री जी के लिये एम0एल0ए0 फ्लैटस में रहना कोई भाोभा की बात नहीं है। मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हूये आपके जरिये अपने मुख्य मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे कोठी नं. 1 में फिर से वापिस जाने का कश्ट करें।

**श्रीमती भांति देवी (कैलाना):** चेयरमैन साहब, हमारे कुछ विधायकों ने यह प्रस्ताव रखा है कि चीफ मिनिसटर साहब, जिन्होंने उस दिन सदन में ऐलायिका था कि मउँ और सभी मंत्री एम0एल0ए0 फ्लैटस में रहेगें, वे एम0एल0एज0 फ्लैटस में बदलने की बजये कोठी नं0 1, सैक्टर-3ए चण्डीगढ़ में ही ठहरे रहें। वैसे तो मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के लिये एम0एल0ए0 फ्लैटस में रहना बडी कठिनाई की बात है, यह हम समझते है। चेयरमैन साहब, जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी ओर हाउस के अन्दर जो मांग की थी वह मुख्य मंत्री और राज्यपाल को छोडकर की गई थी। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी इच्छा से कोठी खाली की

ओर फ्लैट में आ गये। इसके लिये इनको जितनी बधाई दी जाए उतनी ही कम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो आदर्श मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसका दूसरे मंत्रियों और हमारे विधायकों पर क्या असर हुआ? यह कई दिन की बात हो चुकी है और प्रैस के अन्दर भी यह चर्चा का विषय बन चुका है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि अपने स्टेटस के अनुसार वे अपने पहले वाले भवन में चले जाएं लेकिन जो मंत्रीगण दो-दो हजार और अढ़ाई हजार रूपये की किराये की कोठियों में रहते हैं वे उन्हें तुरन्त खाली करके छोटी कोठियों में चले जायें। इस चीज का फौरन डिस्मिशन लेना चाहिये। चेयरमैन साहब, मेरा विधायक से भी पुरजोर अनुरोध है कि उन्हें अगर चेयरमैनशिप छोड़नी पड़े तो मुख्य मंत्री महोदय का आदर्श अपनाना चाहिये। (व्यवधान) मैं चौधरी संत कंवर से प्रार्थना करती हूँ कि वे इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अगर वे अच्छा उदाहरण पैदा करेंगे तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। हम लोगों को तो जनता के सामने एक उदाहरण पैदा करना चाहिये।

**चौधरी संत कंवर:** चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। बहन जी ने मेरी चेयरमैनी के उपर कुछ बात कही हैं इसके लिये जरूरी बात है कि मैं भी अपनी दो बात कहूँ। मैं बहन जी के नोअिस में लाना चाहता हूँ कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तब से इन पांच महीनों में 32 लाख रूपये का फायदा कारपोरेट्स को हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जिम्मेदारी मेरे उपर

डाली है उस जिम्मेदारी को मैं पूरे तरीके से निभा रहा हूँ और जब भी चीफ़ मिनिस्टर साहब चाहेगें तभी मैं इस जिम्मेदारी को छोड़ दूंगा।

**श्री लहरी सिंह मेहरा:** चेयरमैन साहब, अभी चौधरी संत कंवर ने कहा है कि पांच महीने की मेरी चेयरमैनशिप के अन्दर कारपोरेट्स को बत्तीस लाख का फायदा हुआ है। क्या वह बतायेगें कि पहले कौन चेयरमैन थे और उनके टाईम में कितना फायदा हुआ था?

**चौधरी संत कंवर:** चेयरमैन साहब, पहले चेयरमैन जे०के० सिंह थे और उसके टाईम में भी कारपोरेट्स को फायदा हुआ था।

**उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन):** माननीय सभापति जी, मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य केवल प्रस्ताव पर ही अपने विचार रखें और इधर उधर की बातें न करें।

**श्री सभापति:** मैं सदस्यगण से यह प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव है उसी पर वे बोलें और इधर-उधर की बात करके सदन का टाईम वेस्ट न करें।

**श्रीमती भांति देवी:** चेयरमैन साहब, मेरा अनुरोध है कि जिन कोठियों में हमारे अधिकारी बैठे हैं वे अपना स्थान ढूँढें और हमारे तमाम मंत्रीगण उन छोटी कोठियों में चले जाएं और उन एम०एल०एज० को डिस्टर्ब न किया जाये जो अपने परिवार के साथ

अपना हक लिये बैठे है। दूसरी बात मैं चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में कहना चाहती हूं। ये हमारे आई0ए0एस0 अफसरों के उपर.....गये है। मैं मानती हूं कि ये जन प्रतिनिधि है लेकिन जब.....

**डा0 मंगल सैन:** चेयरमैन साहब, .....वाला भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**श्री सभापति:** थोपना भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**श्रीमती भांति देवी:** चेयरमैन साहब, मैं कह रही थी कि मुख्य मंत्री जी अपनी कोठी में चले जाए और जो दूसरे मंत्रीगण है वे छोटी कोठियों में चले जायें.....

**चौधरी राजेन्द्र सिंह:** आन ए प्वांयट आफ आर्डर। चेयरमेन साहब, मैं निवेदन करूंगा कि जिन विधायकों ने यह रैजोल्यूशन मूव किया है उन्हें कम से कम दो-दो मिनट बोलने का टाईम दिया जाये।

**श्रीमती भांति देवी:** चेयरमैन साहब, मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जो एम0एल0एज0 फ्लैट्स में रहते है उनको डिस्टर्ब न किया जाये और मुख्य मंत्री महोदय अपनी उसी कोठी में चले जाये।



**चौधरी हुक्म सिंह (दादरी):** चेयरमैन साहब, चौधरी भागी राम ने जो यह रैजोल्यूशन पे किया है इसका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी कोठी में वापिस चले जाना चाहिये क्योंकि उनके फ्लैट में रहने से कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो यह है कि सिक्क्योरिटी प्वांयट आफ व्यू से भी यहां रहना ठीक नहीं है। हमारे पुलिस कर्मचारियों को यहां दिक्कत आती है। फ्लैट में जगह थोड़ी होती है और जो लोग इनके पास आयेंगे उनको बैठने के लिये कोई जगह नहीं है। अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। बाहर टेंट लगाना पड़ेगा और बाहर लू में जनता परेशान होगी और कोई जगह ऐसी है नहीं जहां पर लोग बैठ सकें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री महोदय फ्लैट में न रहें। दूसरी बात बहन भान्ति देवी ने कही कि हमारे मन्त्रियों को छोटी कोठियों में चले जाना चाहिये जिससे कि खर्च कम हो। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि जो सरकारी कोठियों हैं उनमें तो वजीर साहिबान रहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कोठियां हैं और जिनका किराया कम है अगर उनमें भी हमारे मिनिस्टर साहिबान रहें तो मैं समझता हूँ कि कोई बुराई की बात नहीं है। हमारा मकसद सरकारी खर्च में बचत करना है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमारा मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रीगण का स्टेटस इतना गिर जाए कि वे एम0एल0ए0 फ्लैट्स में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिये। चेयरमैन साहब, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ।

**चौधरी ई वर सिंह (गुहला-अनुसूचित जाति):** चेयरमैन साहब, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फ्लैट में रहकर सादगी का बहुत बड़ा सबूत दिया है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तथा और कई बातों को देखते हुये उनका वहां रहना ठीक नहीं है ओर उनको वापिस अपनी कोठी में चले जाना चाहिये और जिन मंत्रियों को छोटी कोठियों में जाने के लिये कहा गया है उनको छोटी कोठियों में चले जाना चाहिये। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

(12.00 बजे) **चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़):** चेयरमेन साहब, हमारे साथी विधायक चौधरी भागी राम जी ने जो रैजोल्यूशन सदन में पेश किया है कि मुख्य मंत्री जी को अपना निवास स्थान एम0एल0एज0 फ्लैट में बदलने की बजाये कोठी नं01, सैक्टर तीन में ही रहना चाहिये, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी काफी बातों में सोर्स आफ इंसपायरेशन रहे हैं लेकिन जहां तक इनका एम0एल0एज0 फ्लैट में जाने का संबंध है वह केवल मुख्य मंत्री जी तक ही सीमित नहीं होना चाहिये। ठीक है मुख्य मंत्री जी एक आदर्श देना चाहते हैं। ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अनदर या राज्य के अन्दर खर्चा कम हो। मुख्य मंत्री जी बहुत ही थोड़े समय में फ्लैट के अन्दर आ गये लेकिन उनके वहां आने से बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किलें केवल एम0एल0एज0 को ही नहीं आई बल्कि

जनता को भी आई है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चूंकि वे डैमोक्रेसी में विवास रखते हैं और सभी लोग यह चाहते हैं कि अगर वे अपने पुराने निवास स्थान पर चले जाएं तो वहां से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिवन चल सकता है। और लोगों की सेवा वहां से ही अच्छी तरह से हो सकती है। मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने पुराने निवास स्थान पर चले जायें। उनहोने जो आदर्श दिया है हम उसको मानते हैं और हम भी कम खर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे।

**चौधरी भाग मल (सढौरा-अनुसूचित जाति):** चेयरमेन साहब, जो रैजाल्यूटिवन पेनसिविका गया है मैं इसके बारे में दो भावद कहना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर सहब ने जो बडी कोठियों मे रहने की परम्परा हटाई है इसके लिये मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन जहां पर आज कल हमारे मुख्य मंत्री जी ने डेरा लगाया है वह एम0एल0एज0 फ्लैटस है और वहां पर जो एम0एल0एज0 अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ में बाधा पडेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि एम0एल0एज फ्लैट में कोई भी मिनिस्टर नहीं आना चाहिये या फिर एम0एल0एज के लिये कोई और जगह दी जाये। एक मेरा सुझाव और है कि हमारे पास कई कोठियां ऐसी है जो पहले डी0सी0 को दी जाती थी इसलिये उनको खाली करवा कर उनमें मिनिस्टर्ज को रखा जाये। ज्यादा न कहता हुआ मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे वापिस अपनी कोठी में चले जाएं।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम):** चेयरमैन साहब, जितने भी हमारे भाई बोले हैं उन सब की यही भावना है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बगैर सोचे अपनी कोठी में वापिस चले जाना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी जब हमारे मुख्य मंत्री जी किसी गांव में जाते हैं तो वे वहां पर आम घरों में रुकते हैं और जहां तक उनकी सादगी का सवाल है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर चौधरी देवी लाल का एक एम0एल0ए0 के तौर पर सवाल नहीं है लेकिन सवाल मुख्य मंत्री का है। इसलिये उनके स्टेटस को देखते हूये, सीकेसी प्वांयट आफ व्यू को देखते हूये तथा सिक्योरिटी प्वांयट आफ व्यू को देखते हुये उन्हें बगैर किसी बात को देखते और हाउस की सैंस को देखते हुये आज ही भाम को अपनी पुरानी कोठी में रिफिट कर लेना चाहिये। धन्यवाद।

**श्री मनी राम (डबवाली—अनुसूचित जाति):** चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जो फ्लैट छोड़ कर आज ही 12 बजे अपनी कोठी में चले जाएं।

**सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी):** चेयरमैन साहब, जिन हमारे साथियों ने यह रैजोल्यूशन मूव किया अगर उनके नाम चेयर की तरफ आ जाते तो बड़ी अच्छी बात थी। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उन सब के नाम पढ़ दूं तो भी कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिये। (विघ्न) यह प्रस्ताव मैंने और मेरे साथियों ने इसलिये रखा कि हाउस में यह बात हो चुकी है कि चीफ मिनिस्टर

ओर मिनिस्टर्ज कोठियां छोड रहे है ओर एम0एल0एज0 से फलैटस छुडवा रहे है ।

**श्री जय नारायण:** चेयरमैन साहब, मेरा पवांयट आफ आर्डर है । कि जिन 13 आदमियों ने यह प्रस्ताव रखा है उनके अलावा दूसरे आदमियों को भी बोलने के लिये टाइम मिलना चाहिये ।

**सरदार सुखदेव सिंह:** चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि अगर ऐसा फैसला करना हो तो वह पहले पार्टी मीटिंग में किया जाये । अगर कोई खर्चा घटाना हो या बढ़ाना हो तो उसके बारे में पहले पार्टी मीटिंग में फैसला किया जाना चाहिये ताकि ज्यादा कन्ट्रोवर्सी पैदा न हो । दो तीन दिन से हम सुन रहे है जनता कुछ कह रही है और एम0एल0एज कुछ कह रहे है । तो मैं हाउस से और मुख्य मंत्री जी से गुजारि । करनाचाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की भावना बहुत ठीक थी लेकिन ऐसा करने से कुछ ऐसी अड़चनें पैदा होगी जोकि ठीक नहीं होगी । इसलिये ज्यादा चर्चा न कते हुये मैं इतना ही कहूंगा कि वे वापिस अपनी कोठी में चले जाये । सारा हाउस यह चाहता है कि आप अपनी कोठी में चले जायें और एम0एल0एज के लिये जो फलैटस बने हुये है उनको डिस्टर्ब न किया जाये । इतना ही कहते हुये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

**चौधरी जगजी सिंह पोहलू (पाई):** चेयरमेन साहब, जो रैजोल्यूशन मूव किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का सवाल है न कि किसी एक आम आदमी का। चीफ मिनिस्टर साहब को सारी स्टेट का काम करना होता है और काम करने के बाद हर एक आदमी को आराम भी चाहिये। यहां पर फ्लैट्स में कोई आराम की जगह नहीं है। इसके अलावा दुसरा स्टाफ भी यहां पर तंग है क्योंकि यहां पर न उनके नहाने के लिये प्रबन्ध है और न खाने के लिये प्रबन्ध है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे वापिस अपनी कोठी में चले जायें, और वहां जाकर अच्छी तरह से काम करे। यहां एम0एल0एज फ्लैट में दिखावा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**कामरेड भांकर लाल (सिरसा):** चेयरमैन साहब, मुझे भी चीफ मिनिस्टर साहब का इस फ्लैट में रहना बुरा लगता है सिक्योरिटी पवायंट आफ व्यू से भी ययहां रहना ठीक नहीं है। इसलिये मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि वे अपनी पुरानी कोठी में चले जायें।

**मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):** चेयरमैन साहब, 13-14 मंत्रियों की तरफ से यह रैजोल्यूशन आया है। इस रैजोल्यूशन की मौजूदगी मैं मेरा कहने का मतलब है मुझे यहां बैठना नहीं चाहिये था मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था कि अगर मेरे पीछे यह प्रस्ताव पास हो गया तो भी ठीक नहीं है अगर रहूँ तो भी

क्या कर सकता हूँ। यह प्रस्ताव हाउस में जो मेरे साथी लाये हैं मैं उनका मंजूर हूँ। (विधान) भावनी तो बड़ी अच्छी है आप सबकी लेकिन जो स्पीचिज हुई है उनसे जाहिर होता है कि सब ने मन बना लिया है कि होस्टल के सामने मुझे रहने नहीं देंगे, एम0एल0एज फ्लैट्स से निकाल कर ही रहेंगे। मेरा मन था फ्लैट में रहने से एम0एल0एज को परेशान नहीं करना था। मेरा मन था एक ही है कि इस हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन के एग्जिट का खर्च हमें कम करना है ताकि हरियाणा की डिवैल्पमेंट हो सके। ये खर्च 1930 से चले आ रहे हैं। उस समय तो उनके सामने एक ही बात होती थी जेल और फांसी। लेकिन हमारा मन था कि इस ऐडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करे और इसके खर्चों को कम करे। इस उद्देश्य को लेकर हम आये हैं कि हरियाणा की डिवैल्पमेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा हरियाणा सारे हिन्दुस्तान में अच्छा हो, तरक्की जदा करे। जो ज्यादा चर्चा कोठियों पर या सुर के सिलसिले में होता है इनकी बाबत हम गौर करेंगे। मैं आपकी भावना को मानते हुये फ्लैट तो छोड़ दूंगा पर जाउंगा छोटी कोठी मैं। इन भावों के साथ मैं अपने माननीय दोस्त से कहूंगा कि वे यदि अपना प्रस्ताव वापिस ले लें तो मैं उनका बड़ा मंजूर हूंगा। (विधान)

**चौधरी संत कवर:** चेयरमैन साहब, चौधरी साहब को बड़ी कोठी में रहना चाहिये। छोटी कोठी में उनको तकलीफ होगी

हरियाणा के लोग उनके पास आते हैं वे कहां बैठेंगे? इसलिये ये उसी कोठी में जायें, निसको इन्होंने छोड़ा है।

**सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):** सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वह इसलिये कि दे 1 के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि मैं छोटे भवन में जाऊंगा लेकिन दे 1 के सिक्योरिटी अफसर जो थे उनहोंने सिक्योरिटी प्वायंट आफ व्यू से बिल्कुल नहीं माना। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था परन्तु सिक्योरिटी प्वायंट आफ व्यू से उनकी बात भी नहीं मानी गई थी।। यहां चौधरी देवी लाल केवल देवी लाल नहीं है यहां मुख्य मंत्री का सबबी है, सीकरेसी के हिसाब से छोटी कोठी में नहीं जाना चाहिये। छोटी कोठी में जब वे टैलीफोन करेगें तो सब सडक पर सुनाई देगा। कल मैं एम0एल0ए0 फलैट गया चौधरी साहब उपर किसी को फोन कर रहे थे वह सडक पर सुनाई दे रहा था यहां तक कि जो गार्ड तम्बू लगा कर बैठे हैं उनको भी सुनाई दे रहा था। मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करें और इस फैसले को बदलें इस हाउसमें जो रैजोल्यूशन लाया गया है उसको मान लें।

**उद्योग मंत्री (डा० मंगल सैन):** चेयरमैन साहब, सारे सदन ने जो भावना व्यक्त की है मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्री जी इसको रिसपॉस देगे। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है मैं उनकी भावना का आदर करता हूँ। परन्तु उनका समर्थन नहीं करता। जब स्वतन्त्रता संघर्ष में प्रवेश किया जाता है तो स्वतन्त्रता की मांग



करने वाले को जेल जाना पड़ता है ,फांसी की डोरी पर झूलना पड़ता है आज मुख् मंत्री जी जिस पद को संभाले हुये है उस पर रहते हुये बडी परे ानियां आती है, उनकी नीति है कि हरियाणा का विकास हो, हमस ब उनकी मं ा के साथ है। उन्होने जो काम किया है एक प्रतीक के रूप में किया है एक सिम्बौलिक कदम उठाया था लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कहेगें कि वे अपनी कोठी में वापस चलें जाये। मैं आज हाउस में आ वासन देता हूं कि आगे आने वाले समय में हमस ब मिनिस्टर टी0ए0, टैलीफोन आदि के खर्च पर ध्यान देगें। हम आ वासन देते है कि ये सब खर्च घटेगें। मैं इस प्रस्ताव के विशय को देखते हुये और अन्य सदस्यों की भावना को देखते हुये मुख्,यमंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वे जिस कोठी से आये है उसी कोठी मे चले जाये।

**चौधरी देवी लाल:** मैं इस संबंध में ज्यादा बहस मुबाहिसा होना मुनासिब नहीं समझता। जब मेरे साथी डिप्टी लीडर ही मेरे साथ न रहे तो क्या हो सकता है इसलिये अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले ले।

**श्री भागी राम:** मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति:** क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है?

**आवाजें:** जी हां।

**प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।**

3. राज्य मे पिछड़ी श्रेणियों के लिये सरकारी और अर्द्ध—  
सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये पदों के आरक्षण सम्बन्धी

**Mr. Chairman:** This resolution stands in the name of Shri Shamsheer Singh Surjewala.

**Industries Minister (Dr. Mangal Sein):** He is not present.

**Mr. Chairman:** As the Hon. Member is not present, the resolution is not moved.

4. डी०एस०पी०जे० के सिलैब इन ग्रेड के वेतन मान एच०सी०एस० (एग्जैक्टिव) के बराबर लोन तथा सिलैब इन ग्रेड पदों की संख्या बढ़ाने सम्बन्धी

**Mr. Chairman:** The next resolution is in the name of Shri Har Swarup Bura. He may please move his resolution.

**चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम):** चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के सिलैब इन ग्रेड के पदों के वेतनमान 1-1-1977 से एच०सी०एस० (एग्जैक्टिव) के बराबर किये जायें और डी०एस०पी०जे० के सिलैब इन ग्रेड के पदों की संख्या बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी जाये।

**श्री सभापति:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन राजय सरकार से सिफारि ा करता है कि डिप्टी सुपरिन्टेडेंट पुलिस के सिलैव ान ग्रेड के पदों के वेतनमान 1-1-1977 से एच0सी0एस0 (एग्जैक्टिव) के बराबर किये जायें और डी0एस0पीज0 के सिलैव ान ग्रेड के पदों की संख्या बढा कर 25 प्रति ात कर दी जाये ।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा:** चयेरमेन साहब, ज्वायंट पंजाब के अनदर, जब से हरियाणा बना है और डी0एस0पीज0 ओर एच0सी0एस0 के ग्रेड बिल्कुल बराबर थे लेकिन 1-1-1977 से एच0सी0एस0 का गेड 400-1250 से रिवाईज करके 700-1300 कर दिया गया लेकिन डी0एस0पीज0 का वही पुरान 400-1250 का है और सिलैव ान ग्रेड के अन्दर एच0सी0एस0 की 20 परसेंट पोस्टों का प्रोविजन रख दिया है और उनके ग्रेड भी 1300-1500 की जगह 1500-1800 कर दिये लेकिन डी0एस0पीज0 के लिये सिलैव ान ग्रेड का प्रोविजन नहीं है उनका वहीं पुराना 400-1250 का ग्रेड है । हरियाणा के अन्दर लगभग 120 के करीब डी0एस0पीज0 है उनमें से सिर्फ दो को ही अभी तक सिलैव ान ग्रेड दिया गया है । चयेरमैन साहब, पंजाब पुलिस कमी ान ने भी अपनी सिफारि ाओं के अन्दर यह बात कही थी कि एच0सी0एस0 और डी0एस0पीज0 की बेसिक ड्यूटीज को अगर कम्पेयर किया जाये तो डी0एस0पीज0 की ड्यूटीज ज्यादा है और बेसिक भी है । इस बात को देखते हुये इनके साथ बहुत ज्यादाती हुई है । यह बात भाायद मेरे साथी महसूस भी करते होंगे कि इनके साथ

कितनी ज्यादाती हुई है। इन लोगों की ड्यूटीज ओर इनके काम को देखते हुये मैं तो यह महसूस करता हूं कि एच०सी०एस० के ग्रेड रिवाइज होने से पहले डी०एस०पीज० के ग्रेड रिवाइज होने चाहिये थे। चेयरमैन साहब, एक और बड़ी अनियमितता दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस रूलज के अनुसार ए०एस०पीज० और डी०एस०पीज० के ग्रेड भी बराबर होने चाहिये क्योंकि उनके काम, उनकी ड्यूटीज की नेचर तथा उनकी जिम्मेदारी बराबर है लेकिन इस ग्रेड रीविजन के अन्दर ए०एस०पीज० और एच०सी०एस० के ग्रेड बराबर कर दिये गये जबकि डी०एस०पीज० के स्केल रिवाइज नहीं किये गये। तो यह बहुत बड़ी अनियमितता है। इस बात को देखते हुये मेरा यह सुझाव है कि जब ए०एस०पीज० ओर एच०सी०एस० के ग्रेड बराबर रखे है तो डी०एस०पीज० के ग्रेड भी इनके बराबर करने चाहिये। इन भावों के साथ मेरी हाउस से प्रार्थना है कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करे।

**श्री दीपचन्द भाटिया(फरीदाबाद):** चेयरमैन साहब, चौधरी हरस्वरूप बूरा जी ने जो रैजोल्यू इन हाउस के सामने रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, उससे हम काम तो खूब लेते है, वे 24 घंटों सर्विस करते है दिन रात सर्विस करते है, उनको न तो अपने बच्चों का ध्यान होता है ओर न ही उनको अपने रि तेदारों का ध्यान होता है। इसलिये मेरी हाउस से प्रार्थना है कि यह रैजोल्यू इन जरूर पास होना चाहिये। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आई०जी० का जो स्टेटस

है वह एक ज्वायंट सैक्रेटरी के बराबर है । इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थन करता हूं कि आई0जी0 का रैंक चुंकि बहुत बडा होता है इसलिये उस सको पावर्ज भी एक सैक्रेटरी के बराबर होनी चाहिये और उसका स्टेटस भी एक सैक्रेटरी के बराबर होना चाहिये । चेयरमैन साहब, इसके अलावा में होम मिनिस्टर साहब से भी एक प्रार्थना करता हूं। इन लोगों के उपर 24 घंटे ला एंड आर्डर को मेनटेन करने की बात आती है और हर वक्त इनके खिलाफ लोग बोलते है । इसलिये मेरी होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि इनकी तनख्वाह का भी ध्यान रखा जाये ओर जो सिलेक्शन ग्रेड है उसका भी ध्यान रखा जाये ताकि इनमें रिटायर की कोई बात नर हो सके । चेयरमैन साहब, एक बात मैं मुख्यमंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि यह जो सिपाही है यह ऐसे ही पडे रहते है उनको रहने के लिये कोई जगह नहीं है और न ही उनको अपनी फैमिली रखने के लिये कोई स्थान है । इस बात की तरफ सभी सर्विसिज में ध्यान दिया जाता है और सभी डिपार्टमेंटस अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते है । इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि इन सब पुलिस वालों के रहने के लिये कमरे जरूर होने चाहिये क्योकि ये भी हमारे ही भाई है । इन भाब्दों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं ।

**श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी):** सभापति महोदय, मेरे भाई चौधरी हरस्वरूप बूरा ने सदन के सामने जो

प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाइ देती हूँ भाई हरस्वरूप बूरा जी को क्योंकि इन्होंने इन दोनों सर्विसिज के पे स्केल के अनदर जो डिसपैरिटी थी उसको इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन के सामने रखा है । सभापति महोदय, जैसा हरस्वरूप बूरा जी ने बताया, जब से यह सर्विसिज बनी थी तब से लेकर सन 69 तक इनके सिलैव इन ग्रेड ओर इनके वेतनमान बिल्कुल एक से चल रहे थे । सन 69 में थोडा सा अन्तर पडा । एच0सी0एस0 (एग्जैक्टिव) वालों का सिलैव इन ग्रेड कुछ बढा दिया गया लेकिन पुलिस सर्विसिज में इससे ज्यादा रिजैन्टमेंट नहीं हुई । परन्तु अन्त तब आया जब 1-4-1977 को बडी गलेरिंग डिसपैरिटी देने के स्केल में कर दी गई । उनका 400-1150 और इनका 700-1300 । इनका सिलैव इन ग्रेड भी बढा दिया । सभापति महोदय, आज पूरे देश में इस चीज का अहसास किया जा रहा है कि रैवेन्यू सर्विसिज के अधिकारी दूसरी सर्विसिज के लोगों को कुछ आने से हल्का महसूस करते है । वैसे यह बात पहले से चली आ रही है एक बार कैरों साबि के समय में भी यह बात चली थी कि डिप्टी कमि नर को अधिकार होगा कि वह एस0पी0 की रिपोर्ट लिखेगा । उन्होंने कहा था ठीक है डी0सी0 एस0पी0 की रिपोर्ट लिखेगा और एस0पी0 डी0सी0 की रिपोर्ट लिखेगा । इससे डी0सी0 बौखला गये और उस प्रस्ताव को वही का वहीं रोक दिया गया था । दुबारा यह प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के समय मं आया और मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कर दिया और रैवेन्यू अथोरिटी के हैड डिप्टी

कमि नर को यह अधिकार दे दिया कि वह एस0पी0 की रिपोर्ट लिखे हालांकि सिमिलर केडर पोस्ट हैं अगर डी0सी0 को रैवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रे टन को चलाने का अधिकार है तो एक एस0पी0 के उपर तमाम कानून ओर व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेवारी है। लेकिन फिर भी कहा गया कि एस0पी0 की रिपोर्ट डी0सी0 लिखेगा ओर लिखता रहा। सभापति महोदय जब यह बात जनता सरकार के नोटिस में आई कि डिप्टी कमि नर एस0पी0 की रिपोर्ट लिखता है तो इसने इस बात को बेजा मान कर इस डिसपैरिटी को समाप्त कर दिया। (विधन) सभापति महोदय, देहली के बारे में आपको पता होगा। वहां पहले एस0पी0 हुआ करते थे लेकिन कुछ दिन पहले उनको पुलिस कमि नर की पोस्ट दी गई। डिप्टी कमि नर और लैफ्टिनेंट गवर्नर रैवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रे टन का काम संभालेंगे। यह सिर्फ यह बताने के लिये किया गया कि वह अपने काम को उतनी ही जिम्मेदारी से निभाता है जितनी जिम्मेदारी से आई0ए0एस0 वाले अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। (विधन) सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुये अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह गुजारि ा करूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने एच0सी0एस0 (ऐग्जैक्टिव) और एच0सी0एस0 (जुडी ि ायल) के पे स्केल में पाई जाने वाली डिसपैरिटी को समाप्त कर दिया था उसी तरह से इस डिसपैरिटी को भी समाप्त कर दे। आपको मालूम है कि एच0सी0एस0 (ऐग्जैक्टिव) के स्केल को एक खास आदमी को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिये उनके स्केल एच0सी0एस0 (जुडी ि ायल) से ज्यादा कर दिये गये थे। जब मुख्य

मंत्री जी के नोटिस में यह बात आई तो उन्होंने एच०सी०एस० (जुडीशियल) के वेतनमान उनके बराबर कर दिये थे। मुझे उम्मीद है कि यह जो दूसरी डिसपैरिटी उनके सामने आई है इसको भी समाप्त करके वे डी०सी०पी० और एच०एस०एस० (एग्जैक्टिव) के वेतनमान एक समान करेंगे और सिलैबल ग्रेड भी उनको उनके बराबर दे देंगे।

**कामरेड भांकर लाल(सिरसा):** चेयरमैन साहब, मैं भी इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूँ। लेकिन एक बात में हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ डी०एस०पी० के बारे में कुछ सोचा जाये वहाँ पुलिस के दूसरे मुलाजिमों जैसे सिपाही, हवलदार और थानेदार आदि के बारे में भी कुछ न कुछ सोचा जाये। इतना ही कह कर मैं अपनी जगह लेता हूँ।

**चौधरी गंगा राम (गोहाना):** चेयरमैन साहब, यह जो प्रस्ताव आया है एच०सी०एस०(एग्जैक्टिव) और डी०एस०पी० के पे—स्केल को बराबर करने के बारे में, इसको मैं समझता हूँ कि पास किया जाना चाहिये और इस फर्क को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिये। चेयरमैन साहब डी०एस०पी० और एस०एच०ओ० वगैरा अपनी ड्यूटी को तो करते ही है वे एच०सी०एस० आफिसरज के साथ भी रात दिन काम किया करते हैं। मैं इसकी एक मिसाल भी देना चाहता हूँ। जिस वक्त सारे हरियाणा में फलड आया उस वक्त एस०डी०ओ० और डी०सी० वगैरा के साथ पुलिस के अफसरान और एस०एच०ओ० वगैरा भी



रात दिन वाहां रहते थे। इसके अलावा ला एंड आर्डर मेनटेन करने के लिये जहां कहीं भी हमारे एस0डी0ओ0 साहेबान जाते है, डी0सी0 साहब जाते है, वहां पुलिस अफसर भी उनके साथ जाते है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस वालों की 24 घंटे ड्युटी लगी रहती है। चेयरमैन साहब, मै तो यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारी सरकार हरियाणा के अन्दर हकीकत में ला एंड आर्डर की पोजी ान को साफ और स्पष्ट रखना चाहती है, अगर यह चाहती है कि यहां किसी किस्म की करप् ान न हो तो पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जानी चाहिये। उनके बच्चों की पढाई का हमें ध्यान रखना चाहिये। इसी तरह से उनकी रिहाइ ा वगैरा काक हमें ख्याल रखना चाहिये। हमें तो यह देख कर हैरानी होती है कि एच0सी0एस0 औफिसर्ज के पीछे नोकरों की लाईन लगी होती है लेकिन पुलिस अफसरों को कोइ नहीं पूछता। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो फ़ैसिलिटीज एच0सी0एस0 औफिसर्ज को देते है वे पुलिस औफिसर्ज को भी अव य मिलनी चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे थानों की हालत बहुत बुरी है। बिल्डिंग टूटी हुई है, रिहाइ ा के लिये मकान नहीं है। ये सारी बातें मैं इसलिये कह रहा हूं ताकि सरकार जो फ़ैसिलिटीज एच0सी0एस0 आफिसर्ज को देती है, वे उन पुलिस आफीसर्ज को भी दे जो दो दो ड्युटीज करते है। वे अपना काम भी करते है और एच0सी0एस0 आफिसर्ज वर्गरा के साथ भी जाते है। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह मांग करता हूं कि अव य ही इनकी तनख्वाह जो है एच0सी0एस0

औफिसर्ज के बराबर कर दी जानी चाहिये और इनको फ़ैसिलीटीज भी उनके समान दी जानी चाहिये ।

**चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई):** चेयरमैन साहब ,हरस्वरूप बूरा जी ने जो रैजोल्यू इन रखा है यह बडा अहम रैजोल्यू इन हैं मै इसकी पूरजोर ताईद करता हूं क्योकि एच०सी०एस० वालों की ओर डी०एस०पीज० दोनों की ड्यूटीज बराबर है । ला एंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये पुलिसवालों का ख्याल रखना जरूरी है । पंजाब में इन लोगों की तनख्वाह बराबर हुआ करती थी । पहले हरियाणा में भी बराबर हुआ करती थी । लेकिन पिछले दिनों मे यह फर्क डाला गया । (विघन) इसलिये मेरी प्रार्थना है कि डी०एस०पीज० को एच०सी०एस० वालों के बराबर कर दिया जाये और जो फ़ैसिलीटीज एच०सी०एस० वालों को हो वही इनको दी जाये । चेयरमैन साहब मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि जो छोटे मुलाजिम है उनकी भी तनख्वाह बढाई जाये । (विघन)

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):** चेयरमैन साहब, चौधरी हरस्वरूप बूरा ने यह रैजोल्यू इन मूव करके वाक्या ही एक ऐसी बात आगे लाने की कोशिश की है जो एक बेइन्साफी थी और अजिसको दूर करना लाजमी था । सदस्यगण जो भी बोले है सबने आने आने विचार व्यक्त किये लेकिन इसमें एक दोबाते में ओर ऐड करना चाहूंगा । पुलिस की हर कैटैगरी की सर्विस कंडीशंस इतनी सख्त है जितनी किसी दिगरकैटैगरी की

नहीं है। होम पौर्टफोलियो मिलने के बाद जगह-जगह मैने थानों को विजिट किया है। मैनें सरप्राइज विजिट भी किये है। थानों की कंडी ांज बहुत बुरी हैं 100-100, 150-150 वसाल की बिल्डिंग बनी हुई है। (विघ्न) कांस्टेबल्ज के रहने के लिये जो बैरेक्स है वे बहुत तंग है। जहां तीन आदमी खप सकते है वहां 6-6 की चारपाइयां डली हुई हैं सरकार ने अब इस तरफ ध्यान देना भुरु किया है। यह सोचती है कि उन बिल्डिंग की हालत सुधारी जाये, जहां जरूरत हो नई बिल्डिंगज बनाई जाये। कांस्टेबल्ज को भी कुछ राहत देने की बात सरकार सोच रही है। जहां तक, चेयरमैन साहब, इस रैजोल्यू ान का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्री जी के म ावरे के साथ मैं इस सदन में यह घोशणा करना चाहता हूं कि इन प्रिंसिपल हमने यह मांग मंजूर कर ली है। पे-स्केल में जो डिसपैरिटी है वह 1-4-1979 से दूर कर दी जायेगी। 77 वाली बात सरकार मानने मे असमर्थ है। (प्र ांसा)चेयरमैन साहब, सरकार के नोटिस में एक बात और आई है। 1-4-1979 से जो डी0एस0पी0 700-1200 के ग्रेड में होंगे उनकी इंकीमेंट 50 रूपये होगी लेकिन जब कोई आई0पी0एस0 फ़ै ा आता है तो उसकी इंकीमेंट 40 रूपये होती है। इस डिसपैरिटी को भी हम रिमूव करने की को ि ा ा करेगें। सैद्धांतिक रूप से यह डिसपैरिटी खत्म करके डी0एस0पीज0 को यह ग्रेड दे दिया जाएगा।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा:** चेयरमैन साहब, अभी-अभी महोदय ने हाउस में अनाउन्स किया है कि डी0एस0पीज0 के ग्रेडज

एच0सी0एम0 के बराबर कर दिये है और वे अप्रैल से लागू कर दिये जायेंगे। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ लेकिन मैं आपके ,सारा उनका ध्यान एक बात की और दिलाना चाहता हूँ कि आई0ए0एस0 के बराबर की जो दूसरी सर्विसिज है जैसे इंजीनियरिंग सर्विसिज और टैक्नोकैटस आदि उनके ग्रेडज बराबरी के होने चाहिये। इन भावों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये)

श्री उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है?

आवाजें: जी हां।

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।

5. फसलों के लाजिमी बीमे के लिये कानून बनाने सम्बन्धी।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुडंगाव): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वह व्यापारिक या गैर-व्यापारिक फसलों के आग, पाला, ओलों, बाढ़ों तथा अन्य कुदरती मुसीबतों के कारण किसानों को होने

वाले ऐसे नुकसान से बचाने के लिये फसलों के लाजमी बीमों के लिये कानून बनाने के लिये यूनियन सरकार से निवेदन करे।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वह व्यापारिक या गैर-व्यापारिक फसलों के आग, पाला, ओलों, बाढ़ों तथा अन्य कुदरती मुसीबतों के कारण किसानों को होने वाले ऐसे नुकसान से बचाने के लिये फसलों के लाजमी बीमों के लिये कानून बनाने के लिये यूनियन सरकार से निवेदन करे।

**चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान:** डिप्टी स्पीकर साहब, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन यहां पर हर साल बाढ़, ओले, आग और दूसरी नैचुरल कैलेमिटीज आती रहती है जिनके कारण से किसानों को नुकसान होता है। सरकार जो थोड़ी बहुत मदद कर पाती है उससे उनकी पूर्ण रूप से सहायता नहीं हो पाती है। अब जो यह रैजोल्यूशन आया है उसमें लिखा है कि फसलों का बीमा किया जावे। आपको पता है कि किसी के घर में चोरी हो जाये, समुद्र में कोई जहाज डूब जाये, एरोप्लेन ऐक्सीडेंट हो जाये तो सब को कम्पनसेशन मिलता है लेकिन किसान जो सारे भारत में सब से अधिक मात्रा में है उसकी फसल यदि नैचुरल कैलेमिटी से बरबाद हो जाती है तो उसके लिये कोई कम्पनसेशन नहीं है। मैं आपके द्वारा सदन को प्रार्थना करता हूँ कि इस रैजोल्यूशन को यूनानिमसली पास

करके गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजा जाये और कृषि का लाजमी बीमा भी किया जाये ।

**चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई):** डिप्टी स्पीकर साहब, ठाकरान साहब ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है फसलों का बीमा किया जाये, उसकी मैं पुरजोर ताईद करने के लिये खडा हुआ हूं। ओले से , आन्धी से या बारि । से या अन्य किसी कारण से यदि किसी किसान की फसल तबाह हो जाती है तो उसका बीमा होना जरूरी है क्योकि किसान का इसके सिवाये दूसरा कोई साधन नहीं होता है। बीमा होने से मुसीबत के समय में उसके बच्चों को राहत मिल सकती है। सरकार को अपनी तरफ से भी अपनी तरफ से भी कोई फंड कियेट करना चाहिये जिसमें एक करोड या दो करोड रूपया हजो ताकि यदि कोई नैचुरल कैलेमिटी से नुकसान हो तो उनको मीट किया जा सके।

**चौधरी संत कवर(हसनगढ़):** डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में जिस प्रस्ताव पर बहस चल रही है मैं इसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। यह प्रस्ताव फसलों के बीमों के बारे में है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर चौधरी देवी लाल की सरकार में फसलों की बीमा करने की स्कीम नहीं लागू हो पाई तो आने वाली कोई भी सरकार इस स्कीम को लागू नहीं कर सकेगी। मेरी चौधरी देवी लाल जी से और ब्रिगेडियर रण सिंह जी से पूरजोर अपील है कि किसानों की फसल का अवय बीमा किया जाना चाहिये। आज गेंहू का एक किला बोने पर उसमें हल का, खाद का, बीज का

और पानी का 800-1000 रुपये के करीब खर्चा आ जाता है। अभी पिछले दिनों जिस तरह से ओले पड़े हैं उससे किसानों के खेतों में कुछ भी नहीं रहा है उन किसानों के खेत में लान भी नहीं रहा है। जिस तरह से दरांती से कटाई करते हैं ऐसी फसल ओलों से तबाह हो गई है। इसी तरह से जब अनाज खलिहान में आ जाता है तो कई बार आग लग जाती है और बेचारा किसान तबाह हो जाता है बाढ़ के दौरान जो फसल तबाह हो जाती है उससे भी किसानों को काफी नुकसान हो जाता है।

**चौधरी गंगा राम:** डिप्टी स्पीकर सहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। समय बहुत कम है इसलिये हर मੈंबर को दो दो मिनट दे दे ताकि सभी को समय मिल जाये।

**चौधरी संत कंवर:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर रण सिंह जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका विचार है कि बीमा करने की स्कीम लागू की जाये। वे कदम बढ़ा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो फसल ओले से तबाह हो जाती है उस फसल का बीमा यिका जाये लेकिन मेरा सुझाव है कि जो भी फसल किसी भी प्रकोप के कारण तबाह होती है उन सब का बीमा होना चाहिये।

**चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम):** डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो रैजोल्यू इन हाउस में आया है यह बहुत पहले आना चाहिये था। आपको पता है कि सारे हरियाणा का दारोमदार कृषि

पर है। आज हमें खुशी है कि हरियाणा के कृषि मंत्री किसान हैं उन्होंने परसों ही सदन को विवास दिलाया है कि बीमा होना चाहिये। आपको पता है कि यदि कोई कारखाना जल जाता है तो उसको पैसा मिल जाता है। किसी कार या ट्रक का यदि ऐक्सीडेन्ट हो जाता है तो उसको पैसा मिल जाता है लेकिन जो फसल बाढ़ के प्रकोप में या अन्य किसी कारण से तबाह हो जाती है उसके एवज में किसानों को कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है। आज हर किसान दो-तीन रूपये किल्ले के हिसाब से देने के लिये तैयार बैठे हैं। इसलिये सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जब भी फसल ओले या बारसात से तबाह हो तो उसको पूरा पैसा दिया जाये। मैं इस रैजोल्यूशन की स्पोर्ट करता हूँ। (विधान) डिप्टी स्पीकर साहब, जो हमारे बैकवर्ड भाई हैं उनका भी ख्याल किया जाये। इन भावों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन की पूरजोर ताईद करता हूँ।

**श्री जगन नाथ (बवानी-खेडा-अनुसूचित जाति):** डिप्टी स्पीकर साहब, जो यह प्रस्ताव ठाकरान साहब ने सदन के सामने पेश किया है, मैं ही नहीं मेरा विचार यह है कि सारा सदन इसकी स्पोर्ट करेगा। इसकी मुखालफित तो कोई कर ही नहीं सकता। इसके अन्दर अग्नि से, पाले से, हेल स्टोर्म से, बाढ़ से यानि 4-5 चीजें दी गयी हैं। जिनसे यदि नुकसान हो तो किसान को कम्पनसे पैसा मिलना चाहिये। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसमें



कातरे से खाई हुई फसल भी भामिल होनी चाहिये। जब पार्टी मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने यह कहा था। कुछ इलाके जो रेगिस्तानी है जैसे गुडगांव या भिवानी जिला के कुछ इलाके है, वहां पर ज्यादा बारि । से भी फसल बिल्कुल नहीं है। इसलिये हाउस में इस बात के लिये भी आना चाहिये कि किसान का कम्पनसे ।न मिलेगा। .....(व्यवधान एवं भाोर).....मैं यह चाहता हूं कि यह प्रस्ताव हाउस में पास हो। पिछली सरकार के समय में भी एक प्रस्ताव पे । किया गया था लेकिन उस समय सिरे नहीं चढ सका। मैं यह चाहता हूं कि किसान की फसल का बीमा अव य होना चाहिये और इसके लिये हमें यह रैजोल्यू ।न पास करना चाहिये।

**चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़):** डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान ने जो एक महत्वपूर्ण रैजोल्यू ।न सदन में पे । किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं । यह बहुत बडी सच्चाई है कि हमारा हरियाणा प्रदे । हर साल बाढ से, ओलों से तथा ओर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहता है जिसकी वजह से किसानों की लाखों एकड भूमि में सुसल खराब हो जाती है। मैं इसमें ज्यादा न बोलते हुये अपने मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में हमारी सरकार सैंट्रल गवर्नमेंअ से फौरन बातचीत करें ओर काप इं योंरेस को लागू करे।

**चौधरी रामकिान (सफीदों):** उपाध्यक्ष महोदय, जो रैजोल्यू आन हमारे माननीय सदस्य चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान ने सदन के सामने रखा है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। मैं मुख्य मंत्री से और इस महकमे के मंत्री ब्रिगेडियर रण सिंह जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसान की जो हालत है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। जितना बुरा हाल किसान का होता है जब बाढ़ आती है या सूखा आता है या ओले पडते है और किसी का नहीं होतता। इसलिये इन हालात को देखते हुये किसान की फसल का बीमा होना अति आवयक है। मैं ज्यादा न कहते हुये सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि किसान की फसल का बीमा होना अति आवयक है, इसलिये इसके जिये जरूरी कार्यवाही की जाये। धन्यवाद। (व्यवधान व भाोर)

**चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैंरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि 5 मिनट कासमय बाकी है और रै गली इसको स्वीप किया जा रहा है जैसे कि इसकी कोई इम्पोटैन्स ही नहीं है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आधे घंटे का समय बढा दिया जाये ताकि मैंबर्ज को बोलने का पूरा मौका मिले ओर तमाम मैंबर्ज इस पर अपने विचार रख सकें।

**आवाजें:** समय बढाने की कोई आवयकता नहीं है।

**श्री भागी राम (ऐलनाबाद-अनुसूचित जाति):** डिप्टी स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव ठाकरान साहब ने सदन के सामने पे र किया है, मैं उसका पूरजोर समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। इसमें मेराएक सुझाव है।

**श्री जय नारायण:** आन ए पवांयट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, यह रैजोल्यू इन तो यूनानीमसली पास हो जाना चाहिये। इसमें टाईम ज्यादा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है।

**श्री भागी राम:** जब कभी फ़ैक्टरी में एक क्वैटल भी नर्मा जल जाता है। तो उसका पूरा पैसा फ़ैक्टरी वाले को मिल जाता है। जमीदार को चाहे उसकी सारी फसल बरबाद हो जाये, लेकिनउसको आज तक कुछ नहीं मिलता हैं मेरी सी०एम० साहब से और ब्रिगेडियर साहब से यह प्रार्थना है कि उसको भी कुछ न कुछ अव य ही मिलना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि इस रैजोल्यू इन को जल्दी से जल्दी पास किया जाये।

**चौधरी लाल सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बारे में एक बहुत ही जरूरी सुझाव देना चाहता हूं। वैसे तो मैं इस रैजोल्यू इन का समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मेरे सुझाव को भी इसमें भामिल कर लिया जाये। मेरा सुझाव यह है

कि इस रैजाल्यू इन में यह बात भी जोड़ ली जाये कि खेती में जो काम आने वाला जानवर बैल है, उसका भी बीमा होना चाहिये।

**चौधरी रिजक राम (राई):** डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हाउस विचार कर रहा हूँ कि किसान को उसकी फसल का कमपनसे इन देने के लिये उसकी फसल का बीमा होना चाहिये। मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है कि मंत्री जी पहले ही इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सन 1962-63 में सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेप इं योरेंस स्कीम लागू करनी चाही थी लेकिन उस वक्त लाईफ इं योरेंस कारपोरे इन ने उस में पार नहीं पडने दिया था। इसलिये मेरा आपसे सुझाव यह है कि आप इस के बारे में कोई न कोई एक्सपर्ट कमेटी बना दे। ताकि कोई अडचनइ स सम्बन्ध में न आये, नहीं तो लाईफ इं योरेंस कारपोरे इन इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होगी। यदि कोई अडचन इस बारे में आती है तो वह कमेटी उस अडचन को दूर करने का प्रयत्न करे।

**कृषि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह):** डिप्टी स्पीकर साहब, जो रैजाल्यू इन मेरे भाई प्रताप सिंह ठाकरान ने हाउस के सामने रखा है मैंने भी इसका स्वागत किया है। 3-4 दिन हुये मैंने सब साहेबान को यह बताया था कि हरियाणा सरकार और खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ओर मैं, इस प्रौब्लम को बहुत ज्यादा इम्पौटेन्स दे रहे हैं। हम यह समझते हैं कि अगर हमारी सरकार

यह काम कर पायी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अन्दर कितनी हिम्मत है, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको करके दिखायेगें, तो हम एक निराली चीज किसान के लिये कर जायेगें। तो मैं आपको यह अ योरेंस देता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें इसके लिये कुछ भी करना पड़े, हम इस स्कीम को पूरा करेगें और इसे सक्सैसफुल करेगें। इसके बारे में आपको यह जानकर खुशी होगी कि कल ही मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हो रही थी तो इनहोने यह कहा कि यह स्कीम तो बहुत अच्छी है, चाहे कुछ भी करो, इसे पार करना चाहिये। इन्होने यह भी कहा कि पैम्लैटस बनाओ और जनता में बांटो ताकि जनता को यह मालूम हो सके कि हम उनके लिये क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा कल को सैरान खत्म हो रहा है। हम सारे लोग आने-अपने हल्कों में जायेगें। वहां पर हम लोगों को बतायें और उन्हें तैयार भी करै। मैं यह चाहता हूं कि आप लोग लोगों को इसके लिये तैयार करने के साथ-2 हमें अपने सुझाव भी भेजें। मैंने खुद कई मीटिंगों में इस बारे में बात की है। मैं पिछले दिनों अपने भाई भागीराम जी के हल्के ऐलनाबाद में गया हुआ था। वहां पर मैंने जमींदारों से बात की। उन्होंने यह कहा कि चाहे जिस तरह से भी हो, इसे पूरा कर दो, हम जितना भी प्रीमियम होगा, देने के लिये तैयार हैं, हमारी तो जान ही निकल जाती है जब बादल होते हैं। जब लोगों में इस तरह का उत्साह होगा तो यह स्कीम बड़ी आसानी से लागू हो सकेगी। एकबात चौधरी रिजक राम जी ने कही। मैं उनहें यह बताना चाहता हूं कि हम दो मीटिंगें तो कर चुके हैं। पिछली

मीटिंग तो तकरीबन आज से एक हफता पहले हुई थी जिसमें जी०आई०सी०, प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट आफ इंडिया ओर दूसरे सब लोग वहां पर आये थे,। जहां तक चौधरी रिजक राम जी के सुझाव का सम्बन्ध है, हमने पहले ही एक स्पैशल कमेटी बना दी है ओर उसने अपना काम करना भी भुरु कर दिया है। एक भाई ने यह कहा था कि एक दो करोड़ रुपया लगाने से काम चल जायेगा लेकिन मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि सिर्फ एक या दो करोड़ रुपये से काम नहीं चलेगा। कम से कम इसके लिये 100 करोड़ रुपये का फंड क्रियेट करना पडेगा तब जाकर उससे 10-12 करोड़ रुपये के ब्याज की आमदनी होगी। 10-12 करोड़ रुपये की प्रीमियम जायेगा तो 24 करोड़ रुपया जी०आई०सी० भी देगी। यहां पर चौधरी हरस्वरूप बूरा या भायद संत कंवर जी ने यह कहा कि हम तो 800 या 1000 रुपये तक प्रीमियम देने के लिये तैयार है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इन अल्फाज के साथ मैं ठकरान साहब से यह दरखास्त करूंगा कि वे इस रैजोल्यूशन को विदड्रा कर लें।

**चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान:** डिप्टी स्पीकर साहब मंत्री महोदय के आवासन को देखते हुये मैं अपना रैजोल्यूशन वापिस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** क्या माननीय सदस्य को अपना रैजोल्यूशन वापिस लेने की अनुमति है?

आवाजें: जी हां ।

प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस लिया गया

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन कल सुब 9.30 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है

**13.00 बजे**

(The Sabha then \*adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 30<sup>th</sup> March, 1979)